

અધ્યાય-III

સામાજિક એવં આર્થિક ક્ષેત્ર (પી એસ યૂજ)

अध्याय-III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (पी एस यूज)

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति

आर्थिक क्षेत्र (सा क्षेत्र 3) में 20 विभाग शामिल हैं। इस खण्ड के कुछ मुख्य विभाग उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और ग्रामीण एवं लघु उद्योग आदि हैं। राज्य में कुल 22 कम्पनियाँ एवं दो सांविधिक निगम हैं। सितम्बर 2013 तक उनके अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य की कार्यरत सा क्षेत्र 3 ने वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 4,042.00 करोड़ का कारोबार किया (*परिशिष्ट 3.1*)। राज्य के सा क्षेत्र 3 की मुख्य गतिविधियाँ ऊर्जा क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं। 31 मार्च 2013 को 24 सा क्षेत्र 3 थे, जिनका विवरण तालिका 3.1.1 में दिया गया है।

तालिका - 3.1.1

सा क्षेत्र 3 के प्रकार	कार्यरत सा क्षेत्र 3	अकार्यरत सा क्षेत्र 3 ¹	योग
सरकारी कम्पनियाँ ²	18	04 ³	22
सांविधिक निगम	02	-	02
योग	20	04	24

इनमें से कोई भी कम्पनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2012-13 में किसी भी कम्पनी का सम्मेलन/ परिसमापन नहीं हुआ था।

3.1.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अधीन सम्पादित की जाती है। धारा 617 के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह है जिसमें सरकार/सरकारों की कम से कम 51 प्रतिशत दत्त पूँजी लगी होती है। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल है। इसके अतिरिक्त एक कम्पनी जिसकी कम से कम 51 प्रतिशत दत्त पूँजी पर सरकार/ सरकारों, सरकारी कम्पनियाँ, सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों के किसी भी सम्मिश्रण का नियंत्रण हो उसे कम्पनी अधिनियम की धारा 619-ब के तहत सरकारी कम्पनी के तुल्य (मान्य सरकारी कम्पनी) समझा जाता है।

सरकारी कम्पनियाँ (जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) के लेखे की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों, जो कि 1956 के कम्पनी अधिनियम की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (नि म ले) द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, के द्वारा की जाती है। ये लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नि म ले द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके अपने विधानों द्वारा नियंत्रित होती है। राज्य के दो सांविधिक निगम हैं दोनों सांविधिक निगमों में से उत्तराखण्ड परिवहन निगम के लिये नि म ले एकमात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा शुरू में नि म ले को वर्ष 2003-04 से 2008-09

¹ अकार्यरत सा क्षेत्र 3 वे हैं जिनकी प्रचालन कार्यविधियाँ बंद कर दी गई हैं।

² 619-ब कम्पनी शामिल हैं।

³ कुम्ट्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, हिल्स फोन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल्स क्वार्टर्स लिमिटेड, यू पी ए आई लिमिटेड (31 मार्च 1991 से परिसमापन में)।

तक के लिए सौंपी गयी थी जिसे नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों के अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 तक विस्तारित किया गया है।

3.1.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षेत्र 3) में निवेश

31 मार्च 2013 को 24 सा क्षेत्र 3 (619-ब कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए) का कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 7,054.25 करोड़ था, जिसका विवरण तालिका 3.1.2 में दिया गया है।

तालिका - 3.1.2

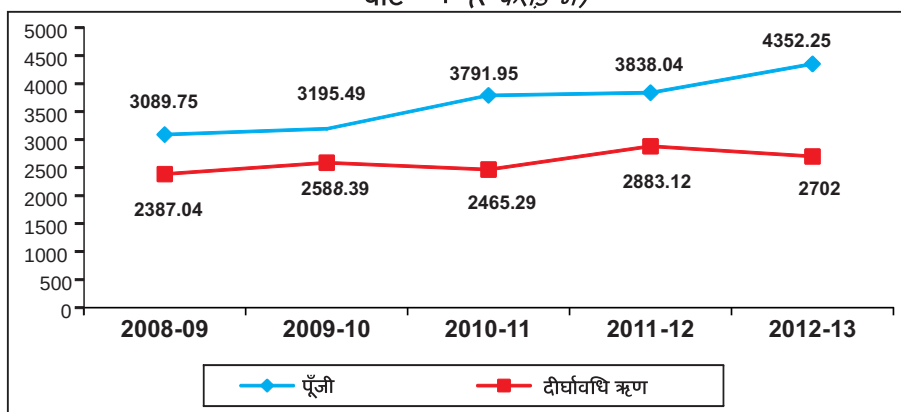
(₹ करोड़ में)

निवेश की प्रकृति	सरकारी कम्पनियाँ		साविधिक निगम	कुल योग
	कार्यरत सा क्षेत्र 3	अकार्यरत सा क्षेत्र 3		
पूँजी	2,240.28	0.38	2,111.59	4,352.25
दीर्घावधि ऋण	2,549.84	-	152.16	2,702.00
योग	4,790.12	0.38	2,263.75	7,054.25

राज्य सा क्षेत्र 3 में सरकारी निवेश के विवरण की सारांशिक स्थिति परिशिष्ट 3.2 में दी गयी है।

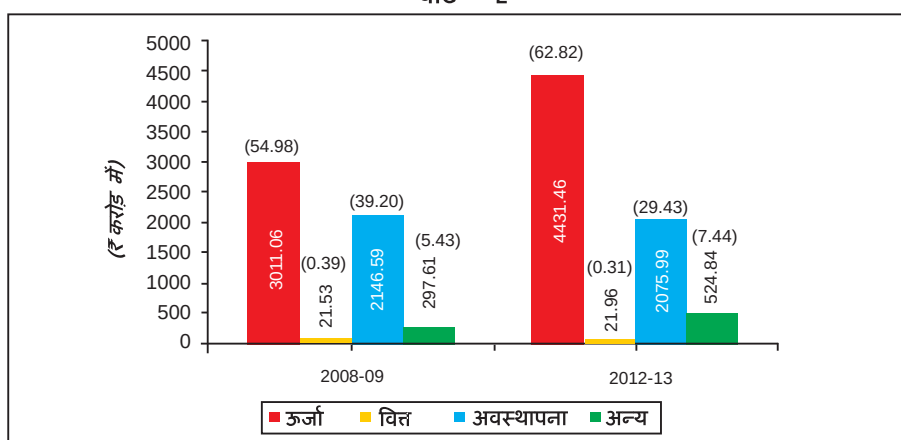
कुल निवेश जो वर्ष 2008-09 के ₹ 5,476.79 करोड़ 28.80 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 7,054.25 करोड़ हो गया था जो निम्न चार्ट-1 में दर्शाया गया है।

चार्ट - 1 (₹ करोड़ में)



31 मार्च 2009 एवं 31 मार्च 2013 के अन्त में अर्थव्यवस्था के विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में निरपेक्ष एवं सापेक्ष दृष्टि से निवेश एवं उनके प्रतिशत निम्न बार चार्ट-2 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट - 2



(कोष्ठकों में आँकड़े कुल निवेश पर खण्डों में निवेश की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

वर्ष 2012-13 के दौरान यद्यपि लगातार मुख्य निवेश का प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र (62.82 प्रतिशत) में जारी रहा, वहीं राज्य के अन्य⁴ क्षेत्रों के निवेश में वृद्धि थी।

3.1.4 बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/ उपदान, गारंटियाँ एवं ऋण

राज्य के सा क्षेत्र 3 से सम्बन्धित इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/ उपदान तथा गारण्टी हेतु बजट से बहिर्गमन क्रम का विवरण *परिशिष्ट 3.3* में दिया गया है। 31 मार्च 2013 को समाप्त तीन वर्षों का सार तालिका 3.1.3 में नीचे दिया गया है।

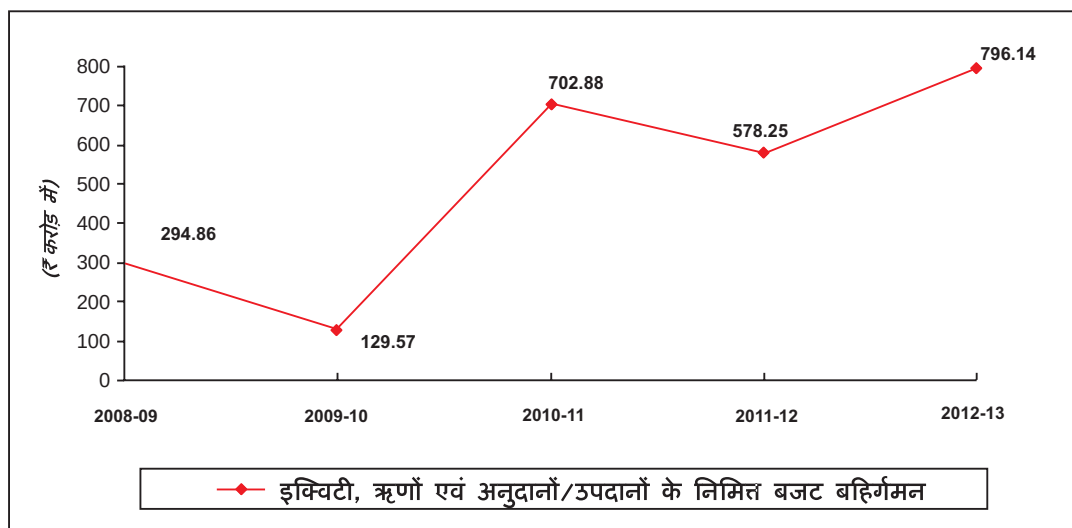
तालिका - 3.1.3

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		सा क्षेत्र 3 की संख्या	राशि	सा क्षेत्र 3 की संख्या	राशि	सा क्षेत्र 3 की संख्या	राशि
1.	इक्विटी पूँजी	3	603.71	4	44.00	2	460.02
2.	ऋण	3	65.70	5	458.02	3	252.90
3.	अनुदानों/उपदान	3	33.47	5	76.23	5	83.22
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	-	702.88	-	578.25	-	796.14
5.	जारी की गई प्रतिभूतियाँ	2	279.98	1	1.35	1	1.51
6.	प्रतिभूति वचनबद्धता	3	289.75	5	1,110.90	4	1,062.93

वर्ष 2012-13 के दौरान वृद्धि मुख्यतः उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत इक्विटी पूँजी के कारण थी। इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/उपदानों के निमित्त बजट बहिर्गमन के क्रम का पिछले पाँच वर्षों का विवरण निम्न *चार्ट-3* में दिया गया है:

चार्ट - 3



राज्य की सा क्षेत्र 3 द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त इक्विटी, ऋण एवं अनुदानों/उपदानों के निमित्त बजटीय बहिर्गमन वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 294.86 करोड़ से ₹ 796.14 करोड़ हो गया था।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष में प्रतिभूति वचनबद्धता की राशि ₹ 289.75 करोड़, (तीन सा क्षेत्र 3) की थी, जो 31 मार्च 2012 को बढ़कर ₹ 1,110.90 करोड़ (पाँच सा क्षेत्र 3) हो गयी तथा 31 मार्च 2013 को घटकर ₹ 1,062.93 करोड़ (चार सा क्षेत्र 3) तक हो गई जैसा कि *परिशिष्ट 3.3* में वर्णित है।

⁴ कृषि एवं समवर्गी, विनिर्माण, सेवाएं एवं विविध।

राज्य सरकार सभी सा क्षेत्र से एक प्रतिशत की दर से तथा भुगतान न करने वाले सा क्षेत्र से एक प्रतिशत अतिरिक्त की दर से प्रतिभूति शुल्क भारित करती है। तथापि, वर्ष 2012-13 में, केवल एक सा क्षेत्र (उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड) ने ₹ 8.47 करोड़ प्रतिभूति शुल्क जो वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित था, का भुगतान किया था। दूसरे सा क्षेत्र जिनकी प्रतिभूति शुल्क जो मार्च 2013 तक ₹ 10.70 करोड़⁵ राज्य सरकार को देय थी और उत्तराखण्ड बहुउद्देश्य वित्त एवं विकास निगम प्रतिभूति शुल्क भुगतान से मुक्त था।

3.1.5 सरकार के वित्त लेखे के साथ मिलान

राज्य सा क्षेत्र के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया प्रतिभूतियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे में दर्शाए गए आँकड़ों से मिलने चाहिए। आँकड़ों के मिलान न हो पाने पर, सम्बन्धित सा क्षेत्र एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2013 को इनकी स्थिति तालिका 3.1.4 में दी गई है:

तालिका - 3.1.4

(₹ करोड़ में)

से सम्बन्धित बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सा क्षेत्र के अभिलेख के अनुसार राशि	अन्तर
इक्विटी	1,819.24	4,328.63	2,509.39
ऋण	213.31	874.99	661.68
प्रतिभूतियाँ	1,041.40	1,062.93	21.53

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 20 सा क्षेत्र के आँकड़ों में अन्तर था और इनमें से कुछ के अन्तरों का मिलान 2003 से लम्बित था। सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों, सा क्षेत्र और वित्त विभाग को प्रत्येक त्रैमासिक में अन्तरों के मिलान की आवश्यक कार्यवाही करनी थी।

3.1.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षेत्र) की कार्यकुशलता

20 कार्यरत सा क्षेत्र में से जिनके लेखे 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त हुए थे में से आठ सा क्षेत्र ने ₹ 102.48 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 12 सा क्षेत्र को ₹ 336.73 करोड़ की हानि हुई। उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 56.47 करोड़) एवं स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 30.01 करोड़) लाभ⁶ अर्जित करने वाले मुख्य सा क्षेत्र थे। उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 218.68 करोड़), डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 30.94 करोड़) एवं किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 25.17 करोड़) एवं पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 7.01 करोड़) हानि⁷ उठाने वाले मुख्य सा क्षेत्र थे। इसके अतिरिक्त जिन सरकारी कम्पनियों और साविधिक निगमों के लेखे सितम्बर 2013 तक अन्तिमीकृत हो चुके हैं, के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम, जिसमें कुल लाभ/हानि, कारोबार, नियोजित पूँजी पर प्रतिफल *परिशिष्ट 3.1* में दिया गया है।

नि म ले प की पिछले तीन वर्षों (2010-12) की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य सा क्षेत्र ने ₹ 1,575.20 का व्यय जो नियंत्रित/बचाया सकता था तथा ₹ 16.32 करोड़ वसूले नहीं गए थे तथा ₹ 21.46 करोड़ अलाभकारी निवेश जो बेहतर प्रबन्धन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। नि म ले प के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का वर्षवार विवरण जो सा क्षेत्र की नमूना जांच पर आधारित है तालिका 3.1.5 में नीचे दिया गया है।

तालिका - 3.1.5

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
अवसूलीय व्यय	3.26	10.78	2.28	16.32
नियंत्रित होने/बचाया जा सकने वाला व्यय	1,283.32	175.46	116.42	1,575.20
अलाभकारी निवेश	-	10.63	10.83	21.46
कुल	1,286.58	196.87	129.53	1,612.98

⁵ यू जे वी एन एल = ₹ 7.16 करोड़, यू पी सी एल = ₹ 2.49 करोड़ और पिटकुल = ₹ 1.05 करोड़।

⁶ उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (2011-12) एवं स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (2011-12) के वर्ष के दौरान के लेखे।

⁷ उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2010-11), डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (2011-12) एवं किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (2011-12) एवं पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (2011-12) के वर्ष के दौरान के लेखे।

वर्ष 2012-13 के दौरान प्रतिवेदन में एक समीक्षा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिसमें ₹ 679.31 करोड़ की धनराशि शामिल है और दो अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर जिसमें ₹ 4.40 करोड़ की धनराशि है को शामिल किया गया है। तथापि शासन द्वारा प्रतिवेदन पर कोई जवाब नहीं दिया गया है (दिसम्बर 2013)।

राज्य सरकार ने सा क्षेत्र के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी जिसके अन्तर्गत सभी सा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई दत्तांश पूँजी पर न्यूनतम लाभांश प्रतिफल का भुगतान आवश्यक होता। उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार आठ सा क्षेत्र ने ₹ 102.48 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया, परन्तु उनके द्वारा लाभांश की घोषणा नहीं की गयी।

3.1.7 लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619-ब के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर कम्पनियों के प्रत्येक वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाना, लेखापरीक्षा एवं विधायिका को प्रस्तुत करना, उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार होता है। कार्यरत सा क्षेत्र के द्वारा संबंधित वर्ष के सितम्बर तक के लेखों को अंतिम रूप दिये जाने की प्रगति का विवरण निम्न तालिका 3.1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका - 3.1.6

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	कार्यरत सा क्षेत्र की संख्या	20	20	20	20	20
2.	वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	13	12	28	15	10
3.	बकाया लेखों की संख्या	135	143	135	140	150
4.	प्रत्येक सा क्षेत्र के अनुसार औसत बकाया (3/1)	6.75	7.15	6.75	7	7.50
5.	कार्यरत सा क्षेत्र जिनके लेखों बकाया हैं	20	20	19	20	20
6.	बकाए की अवधि	1 से 22 वर्ष	1 से 23 वर्ष	1 से 24 वर्ष	1 से 25 वर्ष	1 से 26 वर्ष

पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान, राज्य सा क्षेत्र के लेखाओं को निपटाने में असफल रहा जिस कारण बकाये में बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान लेखाओं के अंतिमीकरण में बकाया लेखों की संख्या 135 से 150 के बीच हो गयी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अकार्यरत सा क्षेत्र के लेखों भी अंतिम रूप दिये जाने हेतु बकाया थे। चार अकार्यरत सा क्षेत्र में से, एक उपक्रम जो कि यू पी ए आई लिमिटेड है, 31 मार्च 1991 से परिसमापन की प्रक्रिया में था तथा शेष तीन अकार्यरत सा क्षेत्र के लेखों, 22 से 26 वर्षों से बकाया थे।

राज्य सरकार ने वर्ष 2005-06 से 2012-13 के दौरान नौ सा क्षेत्र में ₹ 1,243.63 करोड़ का निवेश किया था (इक्विटी: ₹ 524.93 करोड़, ऋण: ₹ 696.26 करोड़ तथा अनुदान ₹ 22.44 करोड़), जिनके लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था, उनका विवरण परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है। लेखों की अनुपस्थिति और बाद में लेखों की लेखापरीक्षा होना यह निश्चित नहीं कर सकती है कि निवेशों और व्यय को लेखों में ठीक प्रकार से लेखाकृत किया, उद्देश्य जिसके लिए निवेश किया गया था प्राप्त हुए हैं या नहीं। इस कारण, सरकारी निवेश जो इन सा क्षेत्र में किया गया है, राज्य विधायिका की जाँच से बाहर रहे।

प्रशासनिक विभागों का दायित्व है कि इन इकाईयों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन सा क्षेत्र के लेखों को निर्धारित समय-सीमा में अन्तिम रूप दिया जाये तथा स्वीकार किये जायें। यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा त्रैमासिक रूप से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग और कर्मचारियों को अ-अन्तिमीकृत बकाया की सूचना प्रेषित की जाती है परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। प्रकरण क्रमशः मुख्य सचिव (फरवरी 2013) तथा प्रमुख सचिव, वित्त (मई 2013), उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से संज्ञान में लाया गया जिससे कि लेखाओं के बकाया का शीघ्रता से समयबद्ध तरीके से परिसमापन किया जा सके।

⁸ कुम्हट्रॉन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, हिल फोन्स लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश हिल्स क्वार्टर्स लिमिटेड।

3.1.8 अकार्यरत सा क्षेत्र 3 का समापन

31 मार्च 2013 को चार अकार्यरत सा क्षेत्र 3 थे। इनमें से, एक सा क्षेत्र 3 ने परिसमापन की प्रक्रिया चालू की है। अकार्यरत सा क्षेत्र 3 के बन्द होने के चरणों को तालिका 3.1.7 में दिया गया है:

तालिका - 3.1.7

क्र.सं.	विवरण	कम्पनियाँ
1.	कुल अकार्यरत सा क्षेत्र 3 की संख्या	04 ⁹
2.	उक्त (1) में से निम्न संख्या	-
(अ)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	01 ¹⁰
(ब)	स्वैच्छिक समापन (परिसमापक नियुक्त)	-
(स)	बन्दीकरण अर्थात् बन्द करने के आदेश/ निर्देश जारी परन्तु परिसमापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई	03

वर्ष 2012-13 के दौरान, कोई भी कम्पनी अन्तिम रूप से बन्द नहीं हुई थी। एकमात्र कम्पनी अर्थात् यू पी ए आई लिमिटेड है, जिसने न्यायालय के आदेशानुसार समापन का मार्ग अपनाया था, 21 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन के अधीन थी।

3.1.9 वार्षिक लेखों पर टिप्पणियाँ

अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान दस कार्यरत कम्पनियों ने अपने 10 लेखापरीक्षित लेखों को अग्रप्रेषित किया। इसमें से 08 लेखाओं को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया तथा दो कम्पनियों को गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किए गये। नि म ले द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं नि म ले की पूरक लेखापरीक्षा इंगित करती है कि लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि म ले की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 3.1.8 में दिया गया है।

तालिका - 3.1.8

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	7	174.57	3	26.04	4	108.47
2.	हानि में वृद्धि	7	247.12	6	234.81	4	86.07
3.	आर्थिक तथ्यों को उद्धोषित न किया जाना	6	1,251.59	2	11.41	1	28.25

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दो कम्पनियों अर्थात् उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (यू एस आई डी सी) एवं किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2011-12 की लेखों जिनको गैर समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया, को छोड़कर सभी आठ (08) लेखाओं को अर्हता प्रमाण¹¹ पत्र प्रदान किए। सरकारी कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जिनकी लेखापरीक्षा अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान की गयी, नीचे दी गई हैं:

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (2011-12)

- प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप अन्य अग्रिम/वसूलियाँ ₹ 80.94 करोड़ जो निजी पार्टियों पर 12 वर्ष से अधिक समय से देय थी की वसूली संदेहास्पद थी।
- भारतीय जीवन बीमा निगम के ऋण ₹ 4.56 करोड़ पर मूलधन तथा ब्याज का पुनर्भुगतान में चूक के लिए दण्डात्मक ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया था।

⁹ कुम्हटौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल्स क्वार्टर्स लिमिटेड तथा यू पी ए आई लिमिटेड।

¹⁰ कम्पनी जो कि यू पी ए आई लिमिटेड है, 31 मार्च 1991 से परिसमापन की प्रक्रिया में थी।

¹¹ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अर्हता प्रमाणपत्र देने का तात्पर्य है कि वित्तीय विवरण में कुछ अपवाद/ अर्हताएँ हैं जिसमें सामान्यतः स्वीकृत लेखाकन के सिद्धान्त का अनुपालन नहीं किया गया है।

- उत्तरप्रदेश सिंचाई विभाग को 2001 से मार्च 2012 की अवधि के लिए जारी ₹ 10.37 करोड़ के देयक विद्युत शुल्क, जिसकी वसूली संदेहास्पद थी, का प्रावधान नहीं किया गया था।

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2010-11)

- सम्पत्तियों का पूँजीकरण ₹ 7.10 करोड़ एवं ह्रास ₹ 6.02 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया।
- ऊर्जा वित्त निगम के लिये ऋण पर ब्याज ₹ 4.05 करोड़ का प्रावधान न किया जाना।
- कम्पनी ने न तो राज्य सरकार को गारन्टी शुल्क दिया न ही एक प्रतिशत दण्डात्मक शुल्क ₹ 1.40 करोड़ का प्रावधान किया।

स्टेट इण्डस्ट्रियल और डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2010-11)

- उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त अनुदान द्वारा निर्मित ₹ 8.10 करोड़ सम्पत्तियों को लेखों में नहीं दर्शाया गया।
- उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त ऋण की अदेयता के कारण दण्डात्मक ब्याज ₹ 1.19 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया।

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (2011-12)

- उत्तराखण्ड सरकार को देय दण्डात्मक गारंटी शुल्क ₹ 3.79 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया।
- ठेकेदार को दिए गए आठ वर्ष से भी पुराने विविध अग्रिम ₹ 2.88 करोड़ जिनकी वसूली संदिग्ध है, का प्रावधान नहीं किया गया।

3.1.10 आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत नि म ले द्वारा जारी किए गये निर्देशानुसार, लेखापरीक्षित कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स) को चाहिए कि आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सम्मिलित करते हुए विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें, जहाँ सुधार की आवश्यकता थी। आठ (08) कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा में संभावित सुधारों पर की गई मुख्य टिप्पणियों का व्याख्यात्मक ब्यौरा नीचे तालिका 3.1.9 में दिया गया है:

तालिका - 3.1.9

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिन पर अनुशंसाएँ की गई	परिशिष्ट-3.2 के अनुसार कम्पनी के क्रमांक का संदर्भ
1.	भण्डार व कलपुर्जों की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का निर्धारण न करना	02	A10, A11
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र का अभाव	07	A1, A5, A10, A13, A14, A16 & A17
3.	मात्रात्मक विवरण, परिस्थितियाँ, पहचान संख्या, अधिग्रहण की तिथि, स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य ह्रास की कीमत एवं उनकी स्थिति आदि को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण को दिखाने वाले अभिलेख का रख रखाव न करना	06	A5, A10, A13, A14, A16 & A17

यह प्रतीत होता है कि सा क्षेत्र को अपने आकार एवं व्यवसाय के हिसाब से सेवा निर्गत देयों, सूचना प्रौद्योगिकी, सामग्री प्रबन्धन इत्यादि के उचित परिणामों के लिए एक उपयुक्त प्रणाली तैयार कर अपनी आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

3.1.11 निगमों के सन्दर्भ में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प प्रति) के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

उत्तराखण्ड परिवहन निगम की लेखापरीक्षा राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत की जाती है जबकि उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा नि म ले को उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 की धारा 52 (3) के अन्तर्गत सौंपी गई है। नि म ले

द्वारा सांविधिक निगमों के लेखाओं पर जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प प्रति) के सरकार द्वारा विधायिका को प्रस्तुतीकरण की स्थिति को नीचे तालिका 3.1.10 में दर्शाया गया है:

तालिका - 3.1.10

क्र.सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिनके लिए पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत नहीं किए गए पृ ले प प्रति का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि	विधानसभा में प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2004-05	2005-06 से 2008-09	29 नवम्बर 2012	उपलब्ध नहीं
2.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2009-10	2010-11	20 जनवरी 2014	उपलब्ध नहीं

3.1.12 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गयी वसूलियाँ

लेखापरीक्षा निष्कर्ष में वे वसूलियाँ भी शामिल हैं, जो सा क्षेत्र के लेखों की नमूना जाँच के दौरान ध्यान में आयी है तथा उन्हें सा क्षेत्र / राज्य सरकार को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा दोबारा जाँच के लिए भेजा जाता है और अधिभुगतान/अधिक भुगतान की स्थिति में वसूली के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान की गयी लेखापरीक्षा में ₹ 58.89 करोड़ की वसूलियाँ विभिन्न सा क्षेत्र के प्रबन्धकों को इंगित किया था, जो सा क्षेत्र द्वारा स्वीकार की गयी। जिसके सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 4.92 करोड़ की वसूली की गयी थी।

3.1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री पर विभागों का प्रत्युत्तर

31 मार्च 2013 में भारत के नि म ले प के प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा 'वितरण कम्पनी की राजस्व संग्रहण दक्षता (यू पी सी एल)' और दो विषयगत अनुपालन लेखापरीक्षाओं, 'यू पी सी एल द्वारा किये गये ऊर्जा क्रय समझौता' तथा 'के एम वी एन के पर्यटन विकास कार्य', को अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों सम्बन्धित विभागों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किये गये कि उसका जवाब छः सप्ताह के अन्दर भेजने का कष्ट करें। यद्यपि सम्बन्धित सा क्षेत्र के प्रबन्धकों द्वारा उत्तर दिये गये, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

3.1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

भारत के नि म ले प का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यह दर्शाता है कि सरकार के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में रखे खातों और अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण की शुरुआत के साथ जाँच की प्रक्रिया की समाप्ति है। यह इसलिए आवश्यक है कि कार्यकारी से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्रकाश में लायी जा सके।

यद्यपि 2009-10, 2010-11 और 2011-12 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका में मार्च 2011, दिसम्बर 2012 और सितम्बर 2013 को प्रस्तुत किये गये। सभी चारों विभागों ने सभी 14 प्रस्तारों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं जिनकी 30 सितम्बर 2013 तक व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी जो तालिका 3.1.11 में दिया गया है।

तालिका - 3.1.11

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक)	प्रस्तुतीकरण की तिथि	प्रतिवेदन में कुल प्रस्तारों/निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तारों/निष्पादन लेखापरीक्षा जिनके व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
2009-10	मार्च 2011	6	6
2010-11	दिसम्बर 2012	5	5
2011-12	सितम्बर 2013	3	3
कुल		14	14

विभागानुसार विश्लेषण जो तालिका 3.1.12 में भी दिया गया है।

तालिका - 3.1.12

विभाग का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
ऊर्जा	3	2	2
विनिर्माण	1	-	1
पर्यटन	1	2	-
निर्माण	1	1	-
कुल	06	05	03

ऊर्जा विभाग मुख्य रूप से व्याख्यात्मक टिप्पणियों को प्रस्तुत न करने के लिए उत्तरदायी था जिसने सभी सात प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की थी।

सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों पर अनुपालन

प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण के छः माह के अन्दर कोपू द्वारा संस्वीकृत कार्यवाही टिप्पणी का जवाब देना होता है कोपू बैठकों की स्थिति, प्रस्तरों जिन पर चर्चा हुई और जो अन्तिमीकृत किये तथा कोपू प्रतिवेदन जो वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (जुलाई 2011) तक जारी हुए, को तालिका 3.1.13 में दिया गया है।

तालिका - 3.1.13

अवधि	बैठकों की संख्या	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा जिस पर चर्चा हुई	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा जो अन्तिमीकृत किये गये	प्रस्तर/निष्पादन लेखापरीक्षा जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2009-10	-	-	-	-	-
2010-11	05	06	06	-	-
2011-12 (जुलाई 2011 तक)	02	02	02	02	-

जुलाई 2011 से कोई भी कोपू की बैठक नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त 34 प्रस्तर चर्चा के लिए बाकी थे जिसमें सबसे पुराना की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001-02 का था। 30 सितम्बर 2013 तक कोई कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त नहीं हुई थी।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट पैरों और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी लेखापरीक्षा आपत्तियाँ और जो उसी समय निस्तारित नहीं हो सकी, को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे 3) के अध्यक्षों तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया जाता है। सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन का जवाब सा क्षे 3 के विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार करवा कर, एक माह के अन्दर प्रेषित किया जाना होता है। मार्च 2013 तक 20 सा क्षे 3 निरीक्षण प्रतिवेदन जो मार्च 2013 तक 20 सा क्षे 3 को जारी किए गये थे, 344 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 1669 प्रस्तर 30 सितम्बर 2013 तक बाकी थे। 30 सितम्बर 2013 को बाकी लेखापरीक्षा आपत्तियों और विभागानुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण *परिशिष्ट 3.5* में दिया गया है।

इसी प्रकार कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा ड्राफ्ट प्रस्तरों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा छः सप्ताह में उन पर टिप्पणी तथा दिये गये तथ्यों की पुष्टि के लिए प्रेषित किया जाता है। अतएव एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और दो विषयगत अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को जुलाई 2013 और सितम्बर 2013 के मध्य दो विभागों¹² को भेजे गये थे।

यह भी संस्तुति की जाती है कि सरकार (अ) निर्धारित समय सारणी के अनुसार कोपू की संस्तुतियों पर निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट प्रस्तरों/कृत कार्यवाही टिप्पणियों (ब) निर्धारित समय सारणी के अन्तर्गत हानि/अदल अग्रिम/अधिक भुगतान (स) लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के प्रत्युत्तर की प्रणाली में सुधार को सुनिश्चित कर सकती है।

3.1.15 सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

राज्य सरकार ने किसी भी सा क्षे 3 के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की कोई योजना नहीं बनायी थी।

¹² ऊर्जा विभाग एवं पर्यटन विभाग।

निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.2 विद्युत वितरण कम्पनी का राजस्व संग्रह

उपभोक्ता को विद्युत प्रदान करने में वितरण प्रणाली विद्युत क्षेत्र की अंतिम कड़ी है। उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) का गठन कम्पनी एक्ट 1956 के प्रावधानों के अनुसार 12 फरवरी 2001 को किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे वर्णित किए गए हैं:

मुख्य अंश

- 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा तय, निर्धारित ऊर्जा नुकसान सीमा के बाद भी उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से ₹ 473.78 करोड़ की ऊर्जा लागत की वसूली नहीं की जा सकी थी।
[प्रस्तर: 3.2.7.1]
- यू ई आर सी की बिजली आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार 'स्टॉप बिलिंग' मामलों का निस्तारण न किए जाने के कारण ₹ 196.07 करोड़ राजस्व की हानि हुई।
[प्रस्तर: 3.2.7.2(i)(अ)]
- उचित क्षमता के विद्युत चालक के उपयोग न करने के कारण कम्पनी को ₹ 3.88 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।
[प्रस्तर: 3.2.7.6]
- कम्पनी द्वारा 1206 उपभोक्ताओं से विद्युत बिलों के विलम्ब भुगतान के कारण ₹ 178.82 करोड़ के विद्युत भार और ₹ 217.39 करोड़ के विलम्ब भुगतान अधिभार की राशि की वसूली नहीं की जा सकी थी।
[प्रस्तर 3.2.8.1(द)]
- 147 बड़े और भारी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में ₹ 17.04 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी थी।
[प्रस्तर: 3.2.8.1(य)]
- वसूली प्रमाण पत्रों के उचित ढंग से अनुश्रवण न किए जाने के कारण 2,539 दोषी उपभोक्ताओं से ₹ 45.51 करोड़ की प्राप्ति नहीं की गई।
[प्रस्तर: 3.2.8.1(ल)]

3.2.1 परिचय

उत्तरांचल राज्य के गठन के परिणामस्वरूप 12 फरवरी 2001 को उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल), पूर्व में उत्तरांचल पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड, का गठन कम्पनी एक्ट, 1956 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। यू पी सी एल (कम्पनी) को 1 अप्रैल 2001 से विद्युत पूर्ति के पारेषण और वितरण क्षेत्र में कार्य करने हेतु यू पी पी सी एल (तत्कालीन उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड) से पृथक किया गया। विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु पारेषण कार्य को अलग करने का आदेश दिया गया। तदनुसार जून 2004 को पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पॉ ट्रा कॉ लि) की स्थापना राज्य में 132 के वी और इससे ऊपर की ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों के अनुरक्षण और संचालित करने के लिए की गई थी। परिणामस्वरूप, यू पी सी एल आज 66 के वी और उससे कम के लाइनों के विद्युत वितरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार की राज्य विद्युत वितरण कम्पनी है। कम्पनी उत्तराखण्ड के 13 जिलों में स्थित 16.96 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की सेवा प्रदाता है। इन विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत के उपयोग की प्रकृति

और उद्देश्य के आधार पर घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि, सरकारी, हल्के उद्योग आदि के रूप में विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

3.2.2 संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल में निहित है जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। कम्पनी के दिन-प्रतिदिन का संचालन निदेशक (परिचालन), निदेशक (परियोजना), निदेशक (वित्त), निदेशक (मानव संसाधन) और मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) की सहायता से प्रबंध निदेशक, जो कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है, द्वारा किया जाता है। कम्पनी के पास कुल 65 इकाई/खण्ड हैं जिसमें से 30 इकाई/खण्ड प्रत्यक्ष रूप से विद्युत के वितरण और राजस्व उगाही के कार्यों में शामिल हैं।

3.2.3 लेखा परीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिए थे कि क्या:

- बिलिंग प्रणाली दक्षतापूर्वक किया गया;
- राजस्व का संग्रह कुशल और प्रभावी था;
- वित्तीय प्रबन्धन यानि राजस्व संग्रह का लेखांकन और उसका बैंक में प्रेषण सही और कुशल था; एवं
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सहित अनुश्रवण तंत्र सही स्थिति में था और प्रभावी था।

3.2.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति

निष्पादन लेखा परीक्षा में वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) द्वारा 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान किए गए राजस्व संग्रह को आच्छादित किया गया है। निष्पादन लेखा परीक्षा का कार्य, मुख्यालय और यू पी सी एल की 30 इकाईयों/खण्डों में से 12¹³ खण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा, अप्रैल और अगस्त 2013 के मध्य सम्पादित की गयी। इन परिचालन इकाईयों का चुनाव राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार "स्ट्रेटिफाईड रैंडम सैम्पलिंग" के साथ "प्रोबेबिलिटी टू साईज विद् रिप्लेशमेन्ट" (पी पी एस डब्लू आर) के आधार पर किया गया था।

लेखा परीक्षा के उद्देश्यों, मानदण्ड और लेखा परीक्षा की पद्धति पर कम्पनी के प्रबंधन के साथ 10 मई 2013 को "प्रवेश गोष्ठी" में विचार-विमर्श किया गया। लेखा परीक्षा निष्कर्षों को कम्पनी और राज्य सरकार को सितम्बर 2013 में सूचित किया गया और 23 अक्टूबर 2013 को "निकास गोष्ठी" में इन पर विचार-विमर्श किया गया। निकास गोष्ठी में प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (परिचालन), निदेशक (परियोजना), मुख्य अभियन्ता (व्यवसायिक) और कम्पनी के अन्य अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा निकास गोष्ठी के दौरान दिए गए विचारों को माना गया और उन्हें उचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

3.2.5 लेखा परीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए अपनाए गए लेखा परीक्षा के निम्नलिखित मानदंड थे :

- विद्युत अधिनियम, 2003 और विद्युत (संशोधित) अधिनियम, 2007 के प्रावधान;

¹³ वि वि ख श्रीनगर; वि वि ख कोटद्वार; वि वि ख हल्द्वानी (नगरीय); वि वि ख हल्द्वानी (ग्रामीण); वि वि ख हरिद्वार (नगरीय); वि वि ख हरिद्वार (ग्रामीण); वि वि ख देहरादून (उत्तर); वि वि ख देहरादून (दक्षिण); वि वि ख देहरादून (मध्य); वि वि ख ऋषिकेश; वि वि ख रुद्रपुर और वि वि ख काशीपुर।

- कम्पनी की वितरण तंत्र के मानक और योजना तथा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा निर्धारित किए गए मापदंड;
- तकनीकी और गैर तकनीकी हानि हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए)/यू ई आर सी/यू पी सी एल द्वारा निर्धारित किए गए मानक;
- यू ई आर सी/यू पी सी एल कम्पनी द्वारा बिलिंग शिड्यूल, दर-सूची, वितरण संहिता और यू पी सी एल की व्यावसायिक राजस्व नियम पुस्तिका पर जारी किए गए दिशा निर्देश/अनुदेश/निदेश/विनियम; और
- सरकार/यू ई आर सी /यू पी सी एल द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेश एवं निदेश।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.6 वित्तीय स्थिति

विगत पाँच वर्षों के (2012-13 को समाप्त हुए) लिए कम्पनी की वित्तीय स्थिति को तालिका 3.2.1 में दिखाया गया है।

तालिका - 3.2.1
कम्पनी की वित्तीय स्थिति का विवरण (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 ¹⁴
1.	अ. देयता					
2.	प्रदत्त पूँजी	5.00	577.00	577.00	577.00	968.91
3.	आरक्षित एवं आधिक्य (पूँजी अनुदान को सम्मिलित करते हुए लेकिन आरक्षित ह्रास को छोड़कर)	1,267.08	1,411.43	1,461.39	208.81	325.56
4.	उधार (ऋण निधियाँ)					
4.1	सुरक्षित	321.65	349.44	332.15	311.28	447.53
4.2	असुरक्षित	825.07	850.20	870.15	636.84	269.39
5.	चालू देयता एवं प्रावधान	2,522.74	2,602.47	3,135.38	4,209.31	4,367.72
6.	अन्य गैर-चालू दायित्व एवं आई यू टी शेष	-	-	-	14.59	11.97
7.	कुल	4,941.54	5,790.54	6,376.07	5,957.83	6,391.08
8.	ब. संपत्तियाँ					
9.	सकल ब्लॉक	2,009.29	2,330.18	2,760.30	1,801.26	2,031.76
10.	घटाओ: ह्रास	860.87	936.05	1,025.71	621.26	678.16
11.	शुद्ध अचल संपत्तियाँ	1,148.42	1,394.13	1,734.59	1,180.00	1,353.60
12.	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	814.39	744.23	579.10	543.84	568.23
13.	निवेश	102.77	162.90	128.27	289.58	442.16
14.	चालू संपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	1,635.56	1,745.23	1,974.00	1,461.43	1,492.38
15.	दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	-	-	-	479.96	469.35
16.	संचित हानियाँ	1,240.40	1,744.05	1,960.11	2,003.02	2,065.36
17.	कुल	4,941.54	5,790.54	6,376.07	5,957.83	6,391.08
18.	ऋण : इक्विटी अनुपात ¹⁵	0.90:1	0.60:1	0.59:1	1.20:1	0.55:1
19.	निवल लागत ¹⁶	31.68	244.38	78.28	-1,217.20	-770.89

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना/विवरण एवं बैलेंस शीट के आधार पर समेकित विवरण)

¹⁴ 2012-13 के सम्बन्ध में आँकड़े अनंतिम हैं।

¹⁵ इक्विटी में प्रदत्त पूँजी एवं आरक्षित और आधिक्य शामिल है।

¹⁶ प्रदत्त पूँजी में आरक्षित और आधिक्य को जोड़कर एवं उसमें से संचित हानियाँ घटाकर।

वर्ष 2012-13 के लिए कम्पनी के लेखे बकाया हैं। इसलिए उपरोक्त तालिका में वर्ष 2012-13 के लिए दिखाए गए आँकड़े अनंतिम हैं। इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान ऋण (सुरक्षित और असुरक्षित) ₹ 1,146.72 करोड़ से घटकर ₹ 716.92 करोड़ हो गए जबकि चालू देयता और प्रावधान अवधि 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 2,522.74 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,367.72 करोड़ हो गए जो यह दर्शाता है कि कम्पनी, कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अल्पकालीन ऋण का सहारा ले रही है।
- 2009-10 की अवधि के दौरान इक्विटी में बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ₹ 572 करोड़ ऊर्जा खरीद बॉन्ड के देयता राशि को इक्विटी में बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्य सरकार द्वारा 2012-13 में ₹ 8.80 करोड़ दिए गए और असुरक्षित ऋण की राशि ₹ 368.11 करोड़ को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, मुक्त विद्युत के सम्बन्ध में ₹ 15 करोड़ की देयता राशि को भी इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।
- 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान कम्पनी का ऋण इक्विटी अनुपात 0.90:1 से घटकर 0.55:1 हो गया। कम्पनी की निवल लागत 2008-09 में ₹ 31.68 करोड़ से घटकर 2012-13 में (-) 770.89 करोड़ हो गई जो दर्शाता है कि विस्तारित हुए समय में संचित हानियों के लगातार जमा होने के कारण कम्पनी की देयता सम्पत्ति से अधिक है।
- कम्पनी की संचित हानियाँ में ₹ 824.96 करोड़ (66.51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो 2008-09 में ₹ 1,240.40 करोड़ से 2012-13 में ₹ 2,065.36 करोड़ हो गई।
- नई संपत्तियों के पूँजीकरण के कारण अचल संपत्तियों के ग्राँस ब्लॉक 2008-09 में ₹ 2009.29 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2,031.76 करोड़ हो गए। कम्पनी द्वारा 2011-12 के दौरान ₹ 1,296.24 करोड़ की संपत्तियाँ भी समायोजित की गई जो सरकारी अनुदानों से सृजित की गई थीं।
- कम्पनी के विविध देनदार ₹ 229.97 करोड़ से बढ़ गए। जो कि 2008-09 के दौरान ₹ 896.73 करोड़ से 2012-13 के दौरान ₹ 1,126.70 करोड़ हो गए थे जो संग्रहण में अक्षमता को इंगित करता है।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार है:

- छ: ¹⁷ वितरण खण्डों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बैंक समाधान विवरण (बैं स वि) मार्च 2013 तक तैयार नहीं किये गये थे। बैंक समाधान विवरण 1 से 17 महीने तक लम्बित थे। मिलान के अभाव में रोकड़ बहियों के प्रारम्भिक अवशेष एवं अन्तिम अवशेष को प्रमाणित नहीं किया जा सका। प्रबन्धन ने टिप्पणी से अपनी सहमति व्यक्त की (अक्टूबर 2013)।
- यह पाया गया कि हरिद्वार ग्रामीण खण्ड में 08-11-2011 से 17-10-2012 के दौरान खण्ड द्वारा बैंक में ₹ 2.32 करोड़ जमा करवाया गया था जिसे बैंक द्वारा कम्पनी के खाते में क्रेडिट नहीं किया गया। खण्ड के संज्ञान में यह तथ्य बैं स वि बनाते समय आया। इस प्रकार बैं स वि को तैयार करने में देरी के कारण ₹ 2.32 करोड़ का गबन हुआ। खण्ड ने सम्बन्धित बैंक मैनेजर (पी एन बी) के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करवाई और अब यह मामला न्यायालय में है। प्रबन्धन ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि मामला बैंक के निदेशक मंडल के पास लंबित है।

¹⁷ रुद्रपुर (बैं स वि लंबित दिसम्बर 2012 से); हरिद्वार (ग्रामीण) (बैं स वि लंबित फरवरी 2013 से); देहरादून (उत्तर) (बैं स वि लंबित जनवरी 2013 से); देहरादून (दक्षिण) (बैं स वि लंबित सितम्बर 2011 से); काशीपुर (बैं स वि लंबित मार्च 2012 से) और ऋषिकेश (बैं स वि लंबित जुलाई 2012 से)।

स) प्रयोग की गई राजस्व प्राप्ति पुस्तिकाओं की वापसी पर एक रजिस्टर के माध्यम से नजर रखी जा सकती है जिसमें जारी की गई एवं वापस की गई पुस्तिकाओं का विवरण अंकित किया जाता हो। तीन खण्डों¹⁸ में यह पाया गया कि 8042 राजस्व प्राप्ति पुस्तकें जो 2009-10 से 2012-13 तक जारी की गई थीं को अगस्त 2013 तक वापस प्राप्त नहीं किया गया था। प्रबंधन ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि उपयोग की गई राजस्व रसीद पुस्तकों के प्रतिपण लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद सितम्बर 2013 में एकत्रित किए गए।

3.2.7 कम्पनी की बिलिंग और राजस्व संग्रह का तंत्र

कम्पनी विद्युत विविध स्रोतों¹⁹ से खरीदती है और विविध उपभोक्ताओं को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा निर्धारित दर सूची के आधार पर अलग-अलग दरों पर उपलब्ध कराती है। प्रचलित दर-सूची के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ता पर विद्युत दर लागू की जाती है। खपत के अनुसार कम्पनी उपभोक्ता को प्रतिमाह/दोमाही बिल प्रस्तुत करती है। बिल राशि के संग्रहण का उत्तरदायित्व कम्पनी के खण्डों पर है। खण्ड द्वारा संग्रहित की गई राशि को कम्पनी के मुख्य प्राप्ति खाते²⁰ में नियमित रूप से हस्तान्तरित किया जाता है। इस प्रकार ऊर्जा की बिलिंग की दक्षता कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा का अधिक से अधिक मात्रा का उपभोक्ता को विक्रय/वितरण करने, वितरण हानि को न्यूनतम करने और अधिकतम राजस्व की प्राप्ति में निहित है। वितरण प्रक्रिया में बिजली की खरीद, बिजली की आपूर्ति, मीटरिंग और बिलिंग, उपभोक्तों से देय की वसूली, राजस्व संग्रहण प्रबंधन, कम्पनी का व्यवसायिक प्रदर्शन और अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण तंत्र सम्मिलित है जिन पर नीचे चर्चा की गई है:

3.2.7.1 विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा का क्रय

राज्य में ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने हेतु कम्पनी के द्वारा विभिन्न स्रोतों से विद्युत का क्रय किया गया था। 2008-09 से 2012-13 के दौरान विद्युत क्रय की कुल इकाईयों और इसके लिए व्यय की गई राशि को तालिका 3.2.2 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.2.2

विद्युत के क्रय पर खर्च राशि का विवरण

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वितरण परिधि पर इकाईयों का क्रय (एम यू में)	7,631.44	8,280.09	9,249.42	10,310.64	10,867.00
विद्युत क्रय (₹ करोड़ में)	1,964.83	2,308.60	2,713.67	3,096.25	3,680.00

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध ऑकड़ों के आधार पर सूचना संकलित।)

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कम्पनी ने 42,253.28 एम यू विद्युत का क्रय लम्बी अवधि के करार से किया था। अन्य 4,826.79 एम यू की व्यवस्था, खुले बाजार से क्रय, अनिर्धारित आदान-प्रदान, छोटी अवधि के करारों और बैंकिंग से की गई थी। ऊर्जा खरीद पर कुल व्यय 2008-09 में ₹ 1,964.83 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 3,680.00 करोड़ हो गया। इसी अवधि में कुल इकाईयों की खरीद 7,631.44 एम यू से बढ़कर 10,867 एम यू हो गई। विद्युत की माँग वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान 7,932.60 एम यू से

¹⁸ श्रीनगर (लंबित राजस्व प्राप्ति पुस्तिका 415: निर्गत अवधि 5/12 से 01/13), ऋषिकेश (लंबित राजस्व प्राप्ति पुस्तिका 5488: निर्गत अवधि 04/09 से 03/13) और कोटद्वार (लंबित राजस्व प्राप्ति पुस्तिका 2139: निर्गत अवधि 04/09 से 03/13)।

¹⁹ उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, सेन्ट्रल पूल का राज्य अंश (टी एच डी सी और एन एच पी सी), राज्य के आई पी पी, खुला बाजार क्रय और अनिर्धारित आदान-प्रदान (यू आई)।

²⁰ मुख्य प्राप्ति खाता कम्पनी का वह खाता है जिसमें खण्डों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व को हस्तांतरित किया जाता है और यह केवल कॉरपोरेट स्तर पर संचालित किया जा सकता है। कम्पनी के एस बी आई, पी एन बी, बी ओ बी और सी बी आई में चार मुख्य प्राप्ति खाते हैं।

बढ़कर 11,478.09 एम यू हो गई। 2008-09 में लंबी अवधि के करार के माध्यम से राज्य में ऊर्जा की आवश्यकताओं को 96.49 प्रतिशत पूरा किया गया जो 2012-13 में घटकर 77.31 प्रतिशत रह गया। लंबी अवधि के करार के माध्यम से विद्युत अधिप्राप्ति की लागत प्रति इकाई ₹ 1.48 से ₹ 3.64 के मध्य थी जबकि यह अन्य स्रोतों के माध्यम से प्रति इकाई ₹ 3.43 से ₹ 7.53 के मध्य थी। परिशिष्ट-3.6 से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी को वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान वितरण हानि यू ई आर सी द्वारा निर्धारित की गई सीमा से अधिक होने के कारण ₹ 473.78 करोड़²¹ का वितरण लागत वहन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया कि कम्पनी की हानियों के मुख्य कारण यू ई आर सी के द्वारा स्वीकार्य विद्युत हानि की सीमा से अधिक विद्युत हानि, एच टी एल टी का खराब अनुपात, ई टी एम का प्रतिस्थापन न होना, मापन का 100 प्रतिशत न होना, अनुपयुक्त चालक का प्रयोग, अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तंत्र और राजस्व प्राप्ति का बकाया का 100 प्रतिशत से कम का वसूली होना था। इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

3.2.7.2 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति

33 के वी स्तर पर हानि को उप-पारेषण हानियाँ कहा जाता है जबकि 11 के वी या उससे कम स्तर पर हानि को वितरण हानि कहा जाता है। हानियाँ तकनीकी और वाणिज्यिक कारणों से हो सकता हैं। तकनीकी हानि बिजली के पारेषण और वितरण हेतु प्रयुक्त अंतर्निहित उपकरणों का प्रयोग एवं कंडक्टर की प्रतिरोधक क्षमता, जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं पर निर्भर है। दूसरी ओर, वाणिज्यिक हानियों के कारण एच टी/एल टी अनुपात की कम प्रतिशतता, खराब मीटर, बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति और विद्युत की चोरी, इत्यादि हैं। विगत पाँच वर्षों 2008-13 तक ऊर्जा हानि के कारण कम्पनी को हुई कुल इकाईयों की हानि, जिसकी वसूली नहीं हो सकी थी, तालिका-3.2.3 में दी गई है:

तालिका-3.2.3

कम्पनी की ऊर्जा हानि का विवरण

(मिलियन यूनिट्स में)

क्रम संख्या	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1.	क्रय की गई ऊर्जा (एम यू में)	7,631.44	8,280.09	9,249.42	10,310.64	10,867.00	46,338.59
2.	विक्रय की गई ऊर्जा (एम यू में)	5,493.73	6,249.21	7,250.68	8,252.72	8,802.00	36,048.34
3.	वितरण हानि (1-2) (एम यू में)	2,137.71	2,030.88	1,998.74	2,057.92	2,065.00	10,290.25
4.	ऊर्जा वितरण हानि की प्रतिशतता (प्रतिशत में) $\{(3/1) \times 100\}$	28.01	24.53	21.61	19.96	19.00	-
5.	वितरण हानि की प्रतिशतता यू ई आर सी द्वारा स्वीकार्य (प्रतिशत में)	22.32	20.32	19.00	18.00	17.00	-
6.	अन्तर (4-5)	5.69	4.21	2.61	1.96	2.00	-
7.	अतिरिक्त वितरण हानियाँ (एम यू में)	434.23	348.59	241.41	202.09	217.34	1,443.66
8.	प्रति इकाई औसत क्रय दर (₹ में)	3.78	4.06	3.99	4.53	4.51	-
9.	प्रति इकाई ²² औसत वसूली (₹ में)	2.91	2.89	3.64	3.67	3.86	-
10.	अतिरिक्त वितरण हानियों का मूल्य (₹ करोड़ में) $\{7 \times 9\}$	126.40	100.67	88.58	74.13	84.00	473.78

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर संकलित सूचना)

²¹ आधिक्य हानि का मूल्य 2008-09 ₹ 126.40 करोड़; 2009-10 ₹ 100.67 करोड़; 2010-11 ₹ 88.58 करोड़; 2011-12 ₹ 74.13 करोड़ और 2012-13 ₹ 84.00 करोड़ = ₹ 473.78 करोड़।

²² प्रति इकाई औसत वसूली की दर = अनुमानित राजस्व/वर्ष के दौरान किये गये बिलिंग को विक्रय ऊर्जा से विभाजित करके (एम यू में)।

यह देखा गया कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान क्रय और वसूली की प्रति इकाई औसत दर का अन्तर 0.35 से 1.17 के बीच था, जिसके परिणामस्वरूप हानियों का संचय हुई।

(i) आपूर्ति की गई विद्युत की मीटरिंग और बिलिंग

यू ई आर सी आदेश (सितम्बर 2003 एवं मई 2012) के अनुसार उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग अनिवार्य है। विद्युत की बिलिंग की कार्य-कुशलता उपभोक्ता को विक्रय की गई विद्युत की 100 प्रतिशत बिलिंग करने पर निर्भर करता है। मीटरों में अभिलिखित विद्युत (मीटर्ड विक्रय) के आधार पर और मूल्यांकन²³ आधार पर कम्पनी उपभोक्ता को बिल प्रस्तुत करती है। गत पाँच वर्षों में कम्पनी द्वारा विक्रय के लिए उपलब्ध कुल विद्युत और बिलिंग की गई विद्युत को नीचे दी गई तालिका-3.2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.2.4

विक्रय की गयी कुल विद्युत और बिल की गई विद्युत का विवरण

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
विक्रय के लिए उपलब्ध विद्युत (एम यू में)	7,631.44	8,280.09	9,249.42	10,310.64	10,867.00
बिल की गई विद्युत (एम यू में)	5,493.73	6,249.21	7,250.68	8,252.72	8,802.00
उपलब्ध विद्युत और बिल की गई विद्युत के मध्य भिन्नता (एम यू में)	2,137.71 (28.01%)	2,030.88 (24.53%)	1,998.74 (21.61%)	2,057.92 (19.96%)	2,065.00 (19.00%)
बिल नहीं की गई विद्युत का वित्तीय मूल्य (करोड़ में)	622.07	586.92	727.54	755.26	797.09
एसेस्ड सेल्स, मीटर्ड सेल्स ²⁴ के प्रतिशतता के रूप में (प्रतिशत में)	2.50	2.45	2.40	2.35	2.25

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर संकलित सूचना।)

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान उपलब्ध विद्युत और बिल की गई विद्युत का अन्तर 1,998.74 एम यू से 2,137.71 एम यू तक था, जिसमें से 2.50 से 2.25 प्रतिशत की बिलिंग वास्तविक उपभोग और लागू दर सूची के अनुसार न करके मूल्यांकन के आधार पर की गयी। मूल्यांकन आधार पर विद्युत विक्रय करने के फलस्वरूप कम्पनी द्वारा वास्तविक उपभोग और लागू दर-सूची के अनुसार राजस्व प्राप्त किये जाने के बजाय औसत आधार पर राजस्व प्राप्त किया जाता रहा।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि मीटर्ड विक्रय और अनुमानित विक्रय सीधे अनुपात में हैं। यह भी बताया गया कि कम्पनी द्वारा कार्यवाही किये जाने के कारण ऊर्जा की अनुमानित बिक्री 2008-09 में 2.50 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 2.25 प्रतिशत हो गई है और भविष्य में यह और भी कम हो जाएगी।

मीटरिंग के मूल्यांकन और विद्युत की बिलिंग की अक्षमताओं के उदाहरण इस प्रकार हैं:

अ) उ वि नि आ की विद्युत आपूर्ति संहिता (अप्रैल 2007) उपबंधित करती है कि कम्पनी ऐसे उपभोक्ता को जो कि देय भुगतान करने में दोषी रहे हों, उन्हें देय राशि का भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय प्रदान करना चाहिए। तत्पश्चात् यदि उपभोक्ता द्वारा छः माह के भीतर पूरे देय का भुगतान नहीं किया जाता है तो स्थायी रूप से विद्युत विच्छेदन कर देना चाहिए।

कम्पनी के 17,000 के सी सी²⁵ उपभोक्ताओं के बिलिंग आँकड़ों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि विभिन्न श्रेणी के 298 उपभोक्ताओं, जिनका बकाया राशि ₹ 5 लाख से ₹ 17.22 करोड़ था, द्वारा 3 महीने से

²³ मूल्यांकन आधार : जहाँ मीटर नहीं लगने या मीटर खराब होने के कारण उपभोक्ता का वास्तविक उपभोग उपलब्ध न हो वहाँ औसत अनुमानित उपभोग के आधार पर बिल प्रस्तुत किए जाते हैं।

²⁴ एसेस्ड सेल्स, मीटर्ड सेल्स के प्रतिशतता के रूप में- यह कम्पनी की कल्पना पर आधारित है।

60 महीनों के बीच की अवधि तक अपना बकाया राशि जमा नहीं कराए गए थे। ऐसे उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन अस्थाई रूप से किया गया था और बिलिंग रोक दी गई थी। मगर कम्पनी द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं की स्थायी रूप से विद्युत विच्छेदन नहीं किया गया और कम्पनी की जापन दिनांक 2 नवम्बर 2004 के प्रावधान के अनुसार संबंधित जिलाधिकारी को वसूली हेतु आवश्यक वसूली प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। परिणामस्वरूप बकाया राशि की वसूली नहीं हो सकी, जो इकट्ठा होकर मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 196.07 करोड़ हो गया, जिसकी वसूली अभी शेष है (अगस्त 2013)।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि वास्तविक राशि और कल्पित राशि को पता करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि दोषी उपभोक्ताओं से कम से कम वास्तविक राशि की वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। यह भी बताया गया कि खण्ड स्तर पर मानक अनुसार त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने की एवं दोषी उपभोक्ताओं से वसूली करने की आदेश जारी कर दिए गए हैं। तथापि, कम्पनी वसूली करने की कार्यवाही करने में विफल रही थी जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में बकाए की राशि पड़ी थी।

ब) कम्पनी की दर अनुसूची (मार्च 2008) यह बताती है कि ऐसे उपभोक्ता (घरेलू एवं पी टी डब्लू के अलावा) जो इलेक्ट्रॉनिक ट्राईवेक्टर मीटर वाले नहीं हैं (ई टी एमस), जिनकी बिलिंग के वी ए एच में नहीं की गई है या जिसके उपयुक्त दर्जों एवं विशिष्टि वाले शण्ट कैपासिटर²⁶ नहीं लगाया है, उनके वर्तमान बिजली के बिल पर 5 प्रतिशत की दर से लो पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया जाना चाहिए। वि वि खण्ड, काशीपुर के अभिलेखों के परीक्षण से यह प्रकट हुआ कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के 42 कनेक्शन 803 के. डब्ल्यू. भार के और स्टेट टयूबवैल के 69 कनेक्शन 900 के. डब्ल्यू. भार के जिसमें कि ई टी एम एवं शण्ट कैपासिटर नहीं लगे थे तथा इनकी बिलिंग के वी ए एच में नहीं की जा रही थी, की वर्तमान बिल पर लो पावर फैक्टर सरचार्ज²⁷ पाँच प्रतिशत की दर से नहीं लिया जा रहा था। जबकि यह केवल के. डब्ल्यू. में बिलिंग की गयी थी। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि खण्ड द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान को अप्रैल 2010 से जनवरी 2013 तक के अवधि के लिए ₹ 260.11 लाख के तथा स्टेट टयूबवैल को अगस्त 2009 से अप्रैल 2013 तक के अवधि के लिए ₹ 67.66 लाख के बिल बिना अधिभार लगाकर जारी किए गए थे। उत्तराखण्ड जल संस्थान के अप्रैल 2008 से मार्च 2010 और स्टेट टयूबवैल के अप्रैल 2008 से जुलाई 2009 तक की अवधि के अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण लेखा परीक्षा द्वारा बकाया धनराशि का आकलन नहीं किया जा सका था। इस प्रकार, अधिभार न प्रभारित करने के परिणामस्वरूप ₹ 16.39 लाख²⁸ की अधिभार कम वसूली हुई।

प्रबन्धन द्वारा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए बताया गया (अक्टूबर 2013) कि संबंधित उपभोक्ता को संशोधित बिल जारी कर दिए गए हैं। यह भी बताया गया कि कम वसूली से बचने हेतु कम्पनी अपनी लागत से शण्ट कैपासिटर स्थापित करेगी और इसकी वसूली उपभोक्ता के बिल से करेगी।

²⁵ की कंजुमर सेल : यह कम्पनी द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं जिनके संबद्ध प्रभार 50 किलो वॉट से ज्यादा हैं; के अनुश्रवण हेतु बनाया गया है। उपरोक्त उपभोक्ताओं में से अधिकांश उपभोक्ताओं के बिलिंग ऑकड़ें मुख्यालय के सर्वर पर उपलब्ध हैं।

²⁶ एक कैपासिटर या कैपासिटर्स का समूह जिसे वोल्टेज में वृद्धि अथवा सर्किट के पावर फैक्टर में सुधार हेतु विद्युत लाइन या विद्युत उपकरण पर स्थापित किया जाता है।

²⁷ पावर फैक्टर उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की प्रतिशतता के डब्ल्यू/के वी ए एच में है। यदि उक्त प्रतिशत 0.85 से नीचे है यह लो पावर फैक्टर माना जाता है।

²⁸ उत्तराखण्ड जल संस्थान के संबंध में (₹ 13.01 लाख) और स्टेट टयूबवैल के संबंध में (₹ 3.38 लाख)।

3.2.7.3 कम्पनी का एच टी-एल टी अनुपात

उच्च एच टी-एल टी अनुपात विद्युत के पारेषण और वितरण में ऊर्जा हानि को कम से कम होना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। औद्योगिक कार्य प्रणाली के अनुसार एच टी और एल टी लाइन का आदर्श अनुपात 1:1 है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2008-13 के दौरान एच टी और एल टी का अनुपात 1 के सापेक्ष लगभग 0.78 रहा। कम्पनी ने 2008-13 के अवधि के दौरान एच टी और एल टी लाइनों के अपने नेटवर्क में क्रमशः 5,102.62 सी के एम²⁹ और 6,500.95 सी के एम की वृद्धि की। कम्पनी द्वारा 2008-13 की अवधि के दौरान एच टी लाइनों की तुलना में एल टी लाइनों के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। कम्पनी को 1:1 अनुपात प्राप्त करने के लिए एच टी और एल टी लाइनों की लम्बाई को समान मात्रा में किये जाने की योजना बनाने की आवश्यकता थी जिससे विद्युत के पारेषण और वितरण तंत्र की कुशलता में सुधार होता और ऊर्जा हानि में कमी आती। हानियों को कम करने का महत्व इस तथ्य से आंका जा सकता है कि एक प्रतिशत हानि को कम करके कम्पनी के राजस्व में ₹ 33.98 करोड़³⁰ जमा किए जा सकते थे।

प्रबन्धन द्वारा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया (अक्टूबर 2013) कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद कम्पनी के पास एच टी/एल टी अनुपात सर्वश्रेष्ठ में से एक थे। यह भी बताया गया कि आर ए पी डी आर पी योजना के कार्यान्वयन के बाद एच टी/एल टी अनुपात में उल्लेखनीय सुधार होगा।

3.2.7.4 उपभोक्ताओं की मीटरिंग

यू ई आर सी के आदेश (सितम्बर 2003 और मई 2012) के अनुसार, उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग अनिवार्य थी। इसके अनुसार गैर-मीटर्ड उपभोक्ताओं के मीटर लगाने का कार्य अगस्त 2012 तक समाप्त किया जाना था हालांकि, अभिलेखों से प्रकट हुआ कि मार्च 2013 तक 16.96 लाख उपभोक्ताओं के सापेक्ष केवल 16.70 लाख मीटरों को लगाया गया था।

प्रबन्धन द्वारा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की गई और कहा गया (अक्टूबर 2013) कि लेखा परीक्षा की टिप्पणी के बाद से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। 1 सितम्बर 2013 तक मात्र 9,679 उपभोक्ता ही गैर-मीटर्ड थे और उनके वहाँ भी दिसम्बर 2013 तक मीटर लगा दिए जाएंगे।

(i) दोषपूर्ण मीटरों के कारण भारी राजस्व की आवर्ती हानि

कम्पनी की दर अनुसूची पर दिनांक 16 फरवरी 2004 के परिपत्र, जो दिनांक 20 सितम्बर 2003 से प्रभावी है, के अनुसार सभी दोषपूर्ण मीटरों को तीन माह के अन्दर प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ऐसा न होने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता (मीटर) और उप खण्ड अधिकारी (वितरण खण्ड) की समान जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के तय लक्ष्यों के अनुसार, दोषपूर्ण मीटरों की संख्या (आई डी एफ, ए डी एफ और आर डी एफ)³¹ कुल उपभोक्ताओं के चार प्रतिशत और पहुँच से बाहर/ रीडिंग नहीं ली गई मीटरों की संख्या सात प्रतिशत होनी चाहिए।

अभिलेखों के परीक्षण से यह पाया गया कि दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन हेतु 3 माह की स्वीकार्य सीमा के बाद भी कुल 16.96 लाख उपभोक्ताओं के विरुद्ध 3,57,622 उपभोक्ताओं³² के मीटर एक से 12 माह तक दोषपूर्ण स्थिति में रहे थे। दोनों क्षेत्रों में आई डी एफ दोषों की संख्या सबसे ज्यादा थी। लेखापरीक्षा में ऐसा

²⁹ सर्किट किलो मीटर्स।

³⁰ (विक्रय ऊर्जा 8,802.00 एम यू × 1/100 × ₹ 3.86 = ₹ 33.98 करोड़), 2012-13 की अवधि के दौरान कम्पनी के वसूली के औसत दर पर आधारित है।

³¹ आई डी एफ= आईडेन्टीफाइड डिफेक्टिव, ए डी एफ= एपियर्स डिफेक्टिव और आर डी एफ= रीडिंग डिफेक्टिव।

³² गढ़वाल क्षेत्र-97,685 (आई डी एफ) + 7,090 (ए डी एफ) + 8,371 (आर डी एफ) + 74,037 (एन ए/एन आर) = 1,87,543
कुमाऊँ क्षेत्र-98,521 (आई डी एफ) + 4,006 (ए डी एफ) + 4,767 (आर डी एफ) + 62,785 (एन ए/एन आर) = 1,70,079 ।

कोई मामला नहीं पाया गया जहाँ पर मीटरों के प्रतिस्थापन में हुए विलम्ब के कारण अधिशासी अभियन्ता/उप-खण्ड अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की गई थी।

प्रबन्धन द्वारा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुआ बताया गया (अक्टूबर 2013) कि खण्डों को पर्याप्त संख्या में मीटर्स उपबल्ल्ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम समय में दोषपूर्ण मीटर बदल दिए जाएं। हालांकि, तथ्य यह बना हुआ है कि निर्धारित समय-सीमा के अनुसार दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन में खण्ड विफल रहे थे।

3.2.7.5 यू ई आर सी के आदेशों का अनुपालन न होने के कारण दण्ड

यू ई आर सी के सितम्बर 2003 के आदेश के अनुसार सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के 100 प्रतिशत मीटरिंग का कार्य मार्च 2005 तक पूर्ण होना था। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकी थी। परिणामस्वरूप, यू ई आर सी ने बिना मीटर के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने के कारण कम्पनी पर ₹ एक लाख की समेकित दण्ड और ₹ 5,000 प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त दण्ड लगाया था (अगस्त 2005)। इसके अतिरिक्त यू ई आर सी द्वारा दिनांक 25 मई 2012 को दिये गये एक अन्य आदेश द्वारा सभी 28,486 बिना मीटर के कनेक्शनों को अगस्त 2012 तक मीटरीकृत करने पर ₹ 5,000 प्रतिदिन की आवर्ती दण्ड को 1 अप्रैल 2011 से माफ करने का निर्णय लिया गया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 100 प्रतिशत मीटरिंग न होने के कारण मार्च 2011 तक कम्पनी ने ₹ 1.04 करोड़ दण्ड के रूप में दिए थे। यह भी देखा गया कि मार्च 2013 तक 0.26 लाख कनेक्शन बिना मीटर के ही चल रहे थे।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए बताया (अक्टूबर 2013) कि 1 सितम्बर 2013 को केवल 9,679 उपभोक्ता ही बिना मीटर के थे और जिनके यहाँ दिसम्बर 2013 तक मीटर लगाने का कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। यह भी कहा गया कि कम्पनी 100 प्रतिशत मीटरिंग होने के बाद यू ई आर सी से दण्ड के रूप में जमा की गई राशि को वापिस करने हेतु अनुरोध करेगी। यद्यपि, यह तथ्यात्मक है कि दण्ड से बचने हेतु कम्पनी को 100 प्रतिशत मीटरिंग निर्धारित समय के भीतर सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

3.2.7.6 अनुपयुक्त विद्युत चालकों का प्रयोग

अतिरिक्त ऊर्जा हानि से बचने हेतु उपयुक्त योग्यता वाले विद्युत चालक का उपयोग किया जाना आवश्यक है। एक विद्युत चालक के विद्युत वाहक क्षमता एक निश्चित तापमान पर काम करने की उसकी बनावट, धातु की क्षमता और उसकी आयु पर निर्भर करती है। विद्युत चालकों की तालिका जो कि आई एस: 398 (1961) पर आधारित है के अनुसार 'डॉंग' विद्युत चालक की विद्युत वाहक क्षमता 45 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान पर 300 एम्पियर तक है।

कम्पनी के दो सब-स्टेशनों ढाकरानी पॉवर हाऊस और सिडकुल की लेखा परीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि कम थर्मल लोडिंग लिमिट³³ वाले विद्युत चालकों के द्वारा धारा का प्रवाह किया जा रहा था। दो फीडर (33 के वी) जो ढाकरानी बिजली घर से निकलकर सेलाकुई और सिडकुल सब-स्टेशनों (11 के वी) पर समाप्त हो रहे थे तथा जिनकी लम्बाई क्रमशः 18.2 और 22.3 किमी थी। ये फीडर्स 'डॉंग' विद्युत चालक पर क्रमशः 320 से 340 और 310 से 320 एम्पियर विद्युत भार क्षमता पर निरंतर कार्य कर रहे थे, जबकि, इस विद्युत भार क्षमता के लिए हाईयर थर्मल लोडिंग लिमिट के विद्युत चालक का प्रयोग किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, अनुपयुक्त क्षमता के विद्युत चालक का प्रयोग करने के कारण, कम्पनी को इन फीडर्स पर मार्च 2010 से

³³ थर्मल लोडिंग लिमिट विद्युत चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता है।

फरवरी 2013 तक की अवधि में स्वीकार्य दो प्रतिशत लाईन लॉस³⁴ के उपरान्त, न्यूनतम दर के आधार पर ₹ 3.88 करोड़³⁵ की अधिक लाईन लॉस हुई।

प्रबन्धन द्वारा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया (अक्टूबर 2013) कि भार के बेहतर प्रबन्धन के लिए लाइन पर नए सब-स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं और यह भी प्रस्तावित किया गया है कि इन फीडरों पर विद्युत चालकों का प्रतिस्थापन किया जाएगा। इस प्रकार, अनुचित क्षमता के विद्युत चालक के उपयोग होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा हानि हुई।

3.2.8 राजस्व संग्रह प्रबन्धन

कम्पनी की राजस्व संग्रह दक्षता बिल की गई ऊर्जा एवं आकलित ऊर्जा के साथ-साथ बकाया राशि को वसूलने में निहित है। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त आय ही कम्पनी की आय का मुख्य स्रोत है। इसलिए राजस्व का शीघ्र एवं त्वरित संग्रह बहुत महत्व रखता है। वर्ष के प्रारम्भ एवं समाप्ति पर बकाया आकलित, संग्रहित तथा शेष बकाया प्राप्ति का विवरण नीचे तालिका 3.2.5 में वर्णित है।

तालिका - 3.2.5

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेष	1,345.18	1,477.26	1,574.84	1,816.75	2,026.35
2.	वर्ष के दौरान बिलिंग/आंकलित राजस्व	1,598.39	1,805.24	2,641.72	3,029.02	3,400.00
3.	वसूली हेतु कुल राशि (1+2)	2,943.57	3,282.50	4,216.56	4,845.77	5,426.35
4.	वर्ष के दौरान वसूली राशि	1,466.31	1,707.66	2,399.81	2,819.42	3,280.00
5.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	1,477.26	1,574.84	1,816.75	2,026.35	2,146.35
6.	वसूली गई राशि की कुल देयता से प्रतिशतता (4/3)	49.81	52.02	56.91	58.18	60.45
7.	महीनों की संख्या के आकलन के संबंध में बकाया (बकाया शेष को आकलित राजस्व से विभाजित (5/2) करने के उपरान्त 12 माह से विभाजित करके)	11.09	10.47	8.25	8.03	7.58

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध ऑकड़ों से संकलित सूचना)

बकाया अवशेषों की वृद्धि के कारणों को अनुच्छेद 3.2.7.2 और 3.2.8.1 में बताये गये हैं। इस प्रकार, 31 मार्च 2013 को बकाया देयों की राशि ₹ 2,146.35 करोड़ थी। वास्तविक देयों के सापेक्ष राजस्व वसूली का प्रतिशत 60.45 था। कम्पनी के वर्ष 2012-13 के उधार (सुरक्षित एवं असुरक्षित) कम्पनी के वर्ष 2012-13 के अन्त के बकाया देयों के 33.40 प्रतिशत के बराबर थे।

प्रबन्धन ने लेखा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की (अक्टूबर 2013)।

3.2.8.1 उपभोक्ताओं से वसूली

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (1) एवं कम्पनी द्वारा नवम्बर 2004 में निर्गत कार्यालय ज्ञापन संख्या 4,421 के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता बिल की देय तिथि से 15 दिन के भीतर विद्युत बकाया जमा नहीं करता है तो उसका कनेक्शन विच्छेदन कर दिया जाना चाहिए तथा 30 दिनों के भीतर धारा 3 के अन्तर्गत उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत बकाया की वसूली को जमा किये जाने हेतु एक डिमाण्ड नोटिस जारी किया जाना चाहिए। यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित अवधि के भीतर बकाया जमा नहीं करता है तो उसके विरुद्ध जिला प्राधिकारियों

³⁴ यू ई आर सी द्वारा पारेषण हेतु अनुमत लाईन लॉस।

³⁵ आगत ऊर्जा: 450.70 एम यू से घटाया प्राप्त ऊर्जा: 423.66 एम यू = 27.04 एम यू से घटाया दो प्रतिशत स्वीकार्य ऊर्जा हानि: 9.01 एम यू = 18.03 एम यू। प्राप्त ऊर्जा में आई शुद्ध कमी = 18.03 एम यू × 10⁶ × ₹ 2.15 (आर टी एस-1 उपभोक्ताओं पर लागू दर) = ₹ 3.88 करोड़।

के माध्यम से धारा 5 के अन्तर्गत वसूली प्रमाणपत्र (आर सी) जारी किये जायेंगे। विद्युत बकाया की वसूली सम्बन्धी सभी कार्यवाही छः माह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। उक्त मानदण्डों के पालन न कर पाने से कम्पनी की बकाया दावों की वसूली की अक्षमता के उदाहरणों पर चर्चा नीचे की गई है:

अ) दस खण्डों में गैर घरेलू/वाणिज्यिक (आर टी एस-2) श्रेणी के 16,195 दोषी उपभोक्ताओं के सापेक्ष केवल 2,023 कनेक्शनों का विच्छेदन किया गया। फरवरी 2013 तक दर्शाये गये उपभोक्ताओं के विरुद्ध ₹ 93.41 करोड़ विद्युत देय बकाया था। इसके अतिरिक्त, यह बकाया 01 से 03 वर्ष तक पुराने थे।

प्रबन्धन द्वारा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए बताया गया (अक्टूबर 2013) कि लेखापरीक्षा की टिप्पणी के पश्चात कम्पनी द्वारा ₹ 15.02 करोड़ विद्युत देय की वसूली कर ली गई है और जितनी जल्दी हो सके शेष धनराशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

ब) कम्पनी के 7 खण्डों में, राजकीय सिंचाई प्रणाली और एल टी एवं एच टी औद्योगिक उपभोक्ता (आर टी एस 5 एवं 7) श्रेणी के अन्तर्गत 76 उपभोक्ताओं के पास ₹ एक लाख से ज्यादा राशि के बकाया 7 माह से 52 माह के दौरान थे। मगर, नियमों के अनुसार उनकी आपूर्ति का विच्छेदन नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही की गई, परिणामस्वरूप, संचित बकाया ₹ 19.80 करोड़ हो गए (मार्च 2013)।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के पश्चात प्रभावी कदम उठाए गए हैं और ₹ 3.83 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। शेष वसूली योग्य धनराशि हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं।

स) वर्ष 2008-09 एवं 2012-13 के दौरान आर टी एस-4 के अन्तर्गत प्राइवेट ट्यूबवेल (पी टी डब्ल्यू) एवं आर टी एस-1 के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं के बकायों में ₹ 69.73 करोड़ की वृद्धि हो गई जिसे तालिका 3.2.6 में दिया गया है।

तालिका-3.2.6

(₹ लाख में)

उपभोक्ताओं की श्रेणी का नाम	वर्ष 2008-09 के लिए विवरण					वर्ष 2012-13 के लिए विवरण				
	कनेक्शनों की संख्या	कनेक्टड भार (के. डब्ल्यू)	विद्युत प्रभार	अधिभार	कुल	कनेक्शनों की संख्या	कनेक्टड भार (के. डब्ल्यू)	विद्युत प्रभार	अधिभार	कुल
पी टी डब्ल्यू	20,624	1,06,615	2,541.35	1,380.39	3,921.74	25,313	1,40,568	4,972.74	1,658.29	6,631.03
घरेलू	11,74,867	13,13,196	22,421.30	9,599.86	32,021.16	12,11,122	17,49,962	22,686.25	13,599.10	36,285.35

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों से संकलित सूचना)

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि समीक्षा अवधि के दौरान पी टी डब्ल्यू उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में केवल 22.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि बकायों में 69.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में उपभोक्ताओं की संख्या में 3.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बकायों में 13.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि आर टी एस-1 श्रेणी के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं से वसूली में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और प्राइवेट ट्यूबवेल उपभोक्ताओं (आर टी एस-4) से रबी/खरीफ की ऋतु में वसूली में बढ़ोतरी हुई है और पूरे प्रदेश में बकाया रहे दावों की वसूली हेतु कैम्प लगाए जा रहे हैं एवं दोषी उपभोक्ताओं के विरुद्ध धारा-5 के अन्तर्गत आर सी जारी की जा रही है।

द) यू ई आर सी द्वारा जारी दर सूची मार्च 2008 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार यदि बिलों का पूर्ण भुगतान देय तिथि के उपरान्त 15 दिनों की रियायत अवधि के दौरान नहीं किया जाता है तो 1.25 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान अधिभार लागू किया जाएगा। यदि सन्दर्भित अधिनियम के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा अधिभार भुगतान नहीं किया जाता है, तो कम्पनी के पास विद्युत आपूर्ति विच्छेदन

का अधिकार है। 12 खण्डों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2013 तक नगरपालिका/नगर निगम, जल निगम, स्टेट ट्यूबवेल, जल संस्थान तथा सार्वजनिक जल निर्माण सहित 1,206 उपभोक्ताओं के विरुद्ध मार्च 2013 तक के ₹ 217.39 करोड़ विलम्ब भुगतान अधिकार के वसूली हेतु लंबित पड़े थे (परिशिष्ट 3.7)। यह भी पाया गया था कि संदर्भित उपभोक्ता ₹ 178.82 करोड़ के विद्युत देय राशि अदा करने में असफल रहे थे।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए बताया (अक्टूबर 2013) कि संबंधित सरकारी विभागों में बजट का प्रावधान बिजली के बिलों का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है। कम्पनी का शीर्ष प्रबंधन बकायों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार से इस मामले का अनुशीलन कर रहा है। आगे यह भी कहा गया था कि जल संस्थान से ₹ 55 करोड़ की वसूली माह अक्टूबर 2013 में हो गई है तथा सिंचाई विभाग से ₹ 26 करोड़ की प्राप्ति माह नवम्बर 2013 में हो जाएगी।

य) यू पी एस ई बी अधिसूचना मार्च 1994 और अप्रैल 2007 से प्रभावी यू ई आर सी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियमन, 2007 में उपबन्धित है कि उन उपभोक्ताओं के सन्दर्भ में जिनको विद्युत आपूर्ति हेतु संयोजन दिया गया है के द्वारा जमा कराई गई अतिरिक्त प्रतिभूति का मूल्यांकन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए, प्रतिभूति 2 माह के औसत उपभोग के बराबर होनी चाहिए। यदि मूल्यांकन की गई प्रतिभूति प्रारम्भिक जमा प्रतिभूति से अधिक है तो दोनों के अन्तर की धनराशि उपभोक्ता से 45 दिन के भीतर नोटिस देकर मांगी जानी चाहिए यदि निर्धारित अवधि के भीतर अतिरिक्त प्रतिभूति जमा नहीं की जाती है तो उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित की जा सकती है। आठ खण्डों के बड़े एवं भारी उपभोक्ताओं के बिल अभिलेखों सम्बन्धित पत्रावली की नमूना जाँच में पाया गया कि 147 उपभोक्ताओं के विरुद्ध ₹ 17.04 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति, वसूली हेतु लंबित (मार्च 2013) थी लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि अतिरिक्त प्रतिभूति की बकाया में से ₹ 3.38 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

(र) यू पी एस ई बी अधिसूचना मार्च 1994 और यू ई आर सी (नये एच टी एवं ई एच टी कनेक्शन को जारी करना, भार की वृद्धि एवं कमी) विनियम, 2007 के अनुसार सभी उपभोक्ताओं के लिए (घरेलू एवं पी टी डब्ल्यू उपभोक्ताओं³⁶ को छोड़ कर) प्रारम्भिक प्रतिभूति को ₹ 1,000 प्रति किलो वाट तक संशोधित करना था। ऐसे सभी उपभोक्ताओं को 30 दिन के भीतर प्रतिभूति जमा करने के लिए नोटिस दिया जाना था जिसमें असफल रहने पर उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित की जा सकती थी। 10 वितरण खण्डों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2013 तक 1,049 उपभोक्ताओं (सभी सरकारी श्रेणियों) के विरुद्ध ₹ 4.46 करोड़ की प्रारम्भिक प्रतिभूति वसूली हेतु लंबित पड़ी थी और इसकी प्राप्ति अगस्त 2013 तक नहीं हो सकी थी।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि सरकारी विभागों को जारी किए गए अधिकतर कनेक्शन काफी पुराने हैं और यू पी एस ई बी के समय का है इन संयोजनों पर प्रारंभिक प्रतिभूति नहीं ली गई थी, और अब कम्पनी प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ता से प्रारंभिक प्रतिभूति का प्रभार ले रही है। प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यू ई आर सी के आदेशानुसार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं से प्रारंभिक प्रतिभूति संग्रह की जानी है और पुराने और नए सरकारी श्रेणी के उपभोक्ताओं को छूट नहीं दी जानी है। इस प्रकार प्रारंभिक प्रतिभूति की प्राप्ति की जानी चाहिए थी।

(ल) 8 खण्डों के अभिलेखों में पाया गया कि जिला मजिस्ट्रेट (डी एम) के माध्यम से ₹ 45.51 करोड़ की वसूली हेतु 2,539 दोषी उपभोक्ताओं के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र (आर सी) जारी किये गए थे। यह पाया गया

³⁶ घरेलू और पी टी डब्ल्यू के लिए प्रारंभिक प्रतिभूति क्रमशः ₹ 400 प्रति किलोवाट और ₹ 100 प्रति किलोवाट है।

कि इन उपभोक्ताओं के विरुद्ध वसूली 1 से 7 वर्षों तक लंबित थी (अगस्त 2013)। इसके अतिरिक्त, खण्डों द्वारा जिलाधिकारियों से न तो पत्राचार किया गया और न ही शीघ्र वसूली हेतु कोई प्रयास किए गए।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि सितम्बर 2013 तक ₹ 1.90 करोड़ की वसूली कर ली गई है और खण्डों द्वारा शेष धनराशि की शीघ्र वसूली/उगाही हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी बताया गया कि चूंकि वसूली जिला प्राधिकारियों के माध्यम से किया जायेगा, प्रबंधन इस विषय को राज्य सरकार के पास शीघ्र वसूली हेतु ले जाएगा।

(व) कम्पनी के कार्यालय आदेश (दिसम्बर 2003) के अनुसार बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के मामले में उनके निर्धारित प्रभार पर 20 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क लगाया जाएगा। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2012-13 के दौरान 1,645 बिना मीटर वाले प्राईवेट ट्यूबवेल उपभोक्ता³⁷, जिनका संयोजन भार 8,898 किलोवॉट था, पर 20 प्रतिशत की दर से ₹ 0.70 करोड़ विद्युत शुल्क नहीं लगाया।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 के अनुसार प्राईवेट ट्यूबवेल उपभोक्ताओं पर विद्युत शुल्क लगाया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रबन्धन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि उपर्युक्त कार्यालय आदेश में दिए गए निर्देशों का वर्ष 2012-13 में पालन नहीं किया गया, जबकि पिछले वर्षों (2008-09 से 2011-12) में विद्युत शुल्क लगाया गया।

(श) कोटद्वार खण्ड में नौ बड़े और भारी/एच टी औद्योगिक उपभोक्ताओं के विरुद्ध न्यूनतम उपभोग गारंटी (एम सी जी), स्वतन्त्र फीडर अधिभार, पर्वतीय विकास छूट (एच डी आर) पर विलम्बित भुगतान अधिभार (एल पी एस) तथा 16 सितम्बर 2001 से प्रभावी दर-सूची में अन्तर से सम्बन्धित ₹ 41.91 करोड़ की विद्युत देय मार्च 2013 तक वसूली हेतु लंबित रहे।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि वर्तमान में यह मामला प्रशासनिक शिकायत जाँच अधिकारी के पास है और उनके द्वारा निर्धारित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

3.2.9 यू ई आर सी के समक्ष वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए आर आर) को प्रस्तुत करना

यू ई आर सी के समक्ष निर्धारित समय में प्रस्तुत वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए आर आर) पर यदि आपत्तियां हो, तो कम्पनी की दर-सूची संरचना में यू ई आर सी द्वारा संशोधन एवं अनुमोदन किया जाता है। कम्पनी को प्रत्येक वर्ष का ए आर आर संबंधित-वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 120 दिन पूर्व दायर करना होता है। यू ई आर सी जनता एवं अन्य हितधारक के सुझाव एवं आपत्तियों पर अच्छी तरह विचार करने के पश्चात् कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन को उन संशोधनों/शर्तों के साथ स्वीकार करती है। कम्पनी पाँच वर्षों में से एक³⁸ वर्ष में नियत तिथि को ए आर आर प्रस्तुत करने में असफल रही। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा 2008-09 का ए आर आर दायर करने में असफल रहने पर आयोग द्वारा स्वयं ही दर निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। अतएव, वर्ष 2008-09 के लिए कम्पनी बढ़ी हुई दर-सूची का लाभ लेने से वंचित रह गई।

लेखा परीक्षा द्वारा दर आदेशों की जाँच में पाया गया कि यू ई आर सी ने 2008-09 से 2012-13 तक विभिन्न खर्चों की राशि को स्वीकृत नहीं किया जैसा कि तालिका 3.2.7 में वर्णन किया गया है:

³⁷ गढ़वाल मण्डल 1,473 उपभोक्ता संबद्ध भार 8,031 किलोवॉट सहित और कुमाऊँ मण्डल 172 उपभोक्ता संबद्ध भार 867 किलो वॉट सहित।

³⁸ 2009-10 के दौरान।

तालिका - 3.2.7

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	अस्वीकृत व्यय
1.	ह्रास	145.22
2.	ऊर्जा खरीद	1,958.31
3.	कार्यशील पूँजी पर ब्याज	70.27
4.	ब्याज प्रभार	32.75
5.	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण का प्रावधान	969.28
6.	ओ एण्ड एम	128.63
	कुल	3,304.46

कम्पनी द्वारा उचित औचित्य न दिये जाने के कारण यू ई आर सी ने उपरोक्त खर्चों को अनुमति नहीं दी। कम्पनी यू ई आर सी के समक्ष अंकेक्षित बैलेंस शीट के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए अनंतिम ड्र-अप एवं वर्ष 2012-13 के लिए अनंतिम ड्र-अप दिसम्बर 2013 तक दायर करने का विचार कर रही है।

3.2.10 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसका आशय संचालन दक्षता, समय से वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव एवं अद्यतन तथा प्रभावी नियमों तथा विधियों के अनुपालन में उचित विश्वास दिलाना है। एक सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण तंत्र गलतियों तथा अनियमितताओं के खतरे को कम करता है। मजबूत प्रबंधन सूचना तंत्र (एम आई एस) भी कम्पनी की गतिविधियों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करने की एक महत्वपूर्ण साधन है जो उच्च प्रबंधन को कम्पनी के कार्यचालन के विषय पर अद्यतन रखते हैं। यह सुधार के क्षेत्र को चिन्हित करने में भी मददगार है। ऐसे विशाल संगठन को अपना संचालन मितव्ययी रूप से दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए एक दक्ष एवं प्रभावी एम आई एस होनी चाहिए। एम आई एस कमियों की पहचान करने एवं बचाव में भी उपयोगी है तथा कम्पनी के भीतर सुगम संवाद को सुनिश्चित करती है।

3.2.10.1 अनुपयुक्त नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पाई गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:-

- कम्पनी के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिससे वह अपने बकाया देय राशि का आयुवार विश्लेषण कर सके। परिणामस्वरूप, यह अपने बकायों की समय पर वसूली हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं कर पाई।
- कम्पनी निर्धारित समय में स्टॉप बिलिंग/अस्थाई विच्छेदन को अंतिम विच्छेदन में नहीं बदल सकी।
- निगरानी संबंधी कोई प्रणाली न बनाए जाने के कारण एवं सभी उपभोक्ताओं के 100 प्रतिशत मीटरिंग और अतिरिक्त/प्रारम्भिक जमा प्रतिभूति की वसूली करने में असमर्थता के कारण कम्पनी लाईन लॉस को रोकने में असफल रही।
- वर्ष 1987 से मार्च 2013 तक राजस्व संग्रहण से संबंधित ₹ 393.63 करोड़ के 482 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित थे। संगठित रूप से मामलों को आगे बढ़ाने एवं अनुसरण करने के लिए केन्द्रीकृत प्रणाली के स्थान पर संबंधित खण्डों के प्रमुखों द्वारा बिना किसी मार्गदर्शन के उनके खुद के पहल पर आगे बढ़ाया गया।

प्रबंधन द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी एक ऐसी प्रणाली को तैयार करने के लिए प्रयासरत है जो कि बकाया राशि की अवधि, स्टॉप बिलिंग मामले तथा अस्थाई विच्छेदन मामलों की पहचान कर सके जिससे की काल्पनिक बकायों राशि को निकाला जा सके। यह भी कहा गया कि सभी उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए दिसम्बर 2013 की समय सीमा निर्धारित की गई है। आगे यह भी कहा गया

कि आर-ए पी डी आर पी योजना के क्रियान्वन के पश्चात लाईन लॉस इत्यादि में सुधार होगा। यह कहा गया कि कम्पनी विभिन्न न्यायालयों में ₹ 393.63 करोड़ के लंबित मामलों के अनुकरण के लिए एक वरिष्ठ कानून अधिकारी को नियुक्त करने की योजना बना रही है।

- v. यू ई आर सी के आदेश (जुलाई 2004) के अनुसार कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करने की, ऊर्जा की मीटरिंग एवं रिडींग सुविधा प्रदान करनी होती है। आयोग ने कम्पनी को निदेश दिया कि उपभोक्ताओं के परिसर से सुविधाजनक दूरी पर संग्रहण केन्द्र का होना सुनिश्चित करे और उन्हें शहरी क्षेत्र में नवम्बर 2004 तक तथा ग्रामीण क्षेत्र में दिसम्बर 2004 तक चेक द्वारा बिजली का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करे। कम्पनी के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि आयोग के आदेश के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए दिसम्बर 2004 में आयोग का एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने पाया (सितम्बर 2005) कि कम्पनी बिलिंग, संग्रहण और दूसरी सुविधाओं के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। आयोग ने कम्पनी पर आदेशों का पालन न करने के लिए ₹ 1.00 लाख का समेकित दण्ड लगाया तथा सितम्बर 2005 से प्रतिदिन ₹ 2,500 का आवर्ती दण्ड भी लगाया जिस पर कम्पनी द्वारा मार्च 2011 तक ₹ 0.52 करोड़ राशि का भुगतान किया गया जबकि मार्च 2013 तक ₹ 0.70 करोड़ का भुगतान देय था।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी द्वारा अपने उपभोक्ताओं के लिए ऑन लाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और दण्ड को माफ करने हेतु आयोग (यू ई आर सी) से अनुरोध कर रही है। तथापि, तथ्य यह है कि यू ई आर सी द्वारा अभी तक दण्ड को माफ नहीं किया गया है।

- vi. विद्युत देयों के बड़े बकायों के केन्द्रीय अनुश्रवण के अभाव में तथा अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण मैसर्स आई डी पी एल³⁹ के विरुद्ध विद्युत देय बकाया मई 1990 से अक्टूबर 2012 के दौरान ₹ 250.28 करोड़ हो गया था। कम्पनी ने बकाया देय राशि को वसूल करने हेतु (फरवरी 2013) बी आई एफ आर⁴⁰, नई दिल्ली से सम्पर्क किया लेकिन बकाया देय-लम्बित हैं (अक्टूबर 2013)। प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि आई डी पी एल से बकाया राशि ₹ 250.28 करोड़ की वसूली के मामले के अनुशीलन हेतु एक समर्पित दल को लगाया जाएगा।

3.2.10.2 निष्प्रभावी सतर्कता व्यवस्था

चोरी/ऊर्जा की हानि के मामलों को कम करने हेतु, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 163 में यह प्रावधान है कि लाइसेंसधारी, उपभोक्ता के परिसर में निरीक्षण और उपकरणों के परीक्षण हेतु प्रवेश कर सकता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 और विद्युत अधिनियम (संशोधित), 2007 के अनुसार, ऊर्जा की चोरी एक दण्डनीय अपराध है। कम्पनी के पास विद्युत के दुरुपयोग/चोरी का पता लगाने और रोकने के लिए अलग सतर्कता खण्ड है। लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी द्वारा निरीक्षण और उपकरणों के परीक्षण हेतु किसी भी लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया था। चयनित की गई 12 इकाईयों में से 8⁴¹ में चोरी से संबंधित मामलों के आँकड़ों का रख-रखाव नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, चार⁴² खण्डों द्वारा आँकड़ों का रख-रखाव सुव्यवस्थित

³⁹ इण्डियन ड्रग्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश।

⁴⁰ बोर्ड फॉर इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रिकन्सट्रक्शन।

⁴¹ देहरादून (उत्तर); देहरादून (मध्य); ऋषिकेश; श्रीनगर; कोटद्वार; हल्द्वानी (ग्रामीण); हल्द्वानी (नगरीय); और हरिद्वार (नगरीय)।

⁴² रुद्रपुर; काशीपुर; देहरादून (दक्षिण) और हरिद्वार (ग्रामीण)।

तरीके से नहीं किया गया था और 2009-11 की अवधि तक के निरीक्षण और मूल्यांकन का विवरण लेखापरीक्षा को विश्लेषण करने हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया था। 2011-13 की अवधि के दौरान कम्पनी के चार खण्डों द्वारा चोरी के मामलों का विश्लेषण और मूल्यांकन तालिका 3.2.8 में विस्तृत रूप में दिया गया है:

तालिका - 3.2.8

चोरी के मामले व मूल्यांकन का विवरण

(₹ लाख में)

खण्ड का नाम	जाँच वर्ष	कुल उपभोक्ताओं की संख्या	जाँचों की संख्या	पकड़े गए चोरी के मामलों की संख्या	प्रत्यक्ष रूप से की गई चोरी	यू यू ई ⁴³ / शण्ट डिटेक्टरेड	प्राथमिकी दर्ज की गई	आंकलित धनराशि	वसूल की गई राशि	शेष
वि वि ख, रुद्रपुर	2011-12	77,353	उपलब्ध नहीं	135	58	77	उपलब्ध नहीं	174.22	38.36	135.86
वि वि ख, काशीपुर	2011-12 और 2012-13	62,588	उपलब्ध नहीं	370	306	64	306	320.47	169.60	150.87
वि वि ख, (दक्षिण), देहरादून	2012-13	64,598	463	222	222	उपलब्ध नहीं	140	135.63	108.65	26.98
वि वि ख, (ग्रामीण), हरिद्वार	2011-12 और 2012-13	49,966	1,076	1,076	561	515	561	284.75	144.26	140.49
कुल	—	2,54,505	1,539	1,803	1,147	656	1,007	915.07	460.87	454.20

(स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से संकलित सूचना)

जाँच की गई (दक्षिण देहरादून और ग्रामीण हरिद्वार) कुल संख्या कुल उपभोक्ताओं की संख्याओं के एक प्रतिशत से भी कम था। यह देखा गया कि हरिद्वार ग्रामीण खण्ड द्वारा की गई निर्धारित जाँच के दौरान चोरी के मामले 100 प्रतिशत पाए गए थे। कुल पकड़े गए 1,803 यू यू ई/शण्ट और प्रत्यक्ष चोरी के मामलों⁴⁴ में से केवल 1,007 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई और ₹ 915.07 लाख के आंकलित धनराशि के विरुद्ध मात्र ₹ 460.87 लाख ही कम्पनी द्वारा दोषी उपभोक्ताओं से वसूल (अगस्त 2013) किए गए थे।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि श्रमशक्ति की कमी के कारण खण्डों द्वारा की गई जाँच पर्याप्त नहीं थी तथा कम्पनी चोरी प्रभावित क्षेत्रों की पहचान का प्रयास कर रही है तथा आर ए पी डी आर पी कार्यक्रम के अंतर्गत ए बी सी⁴⁵ विद्युत चालक लगाए जाएंगे तथा क्षेत्र की बेहतर जाँच के लिए दोहरी मीटरिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। दोषी उपभोक्ताओं से कम वसूली होने के सन्दर्भ में यह कहा गया कि संबंधित उपभोक्ताओं के न्यायालय में अपील करने के कारण वसूली लम्बित रही।

निष्कर्ष

कम्पनी की जमा हुए हानि वर्ष-प्रति वर्ष बढ़ती रही। बिलिंग और संग्रह की प्रक्रियाएं अप्रभावी थीं क्योंकि कम्पनी ऊर्जा की लागत तक लाईन हानियों को कम करके वसूल नहीं कर सकी थी जो कि चोरी, बिना मीटर के आपूर्ति, मीटरों की सत्यता न सुनिश्चित किया जाना और चोरी प्रकरण क्षेत्रों की पहचान न किया जाना था। कम्पनी सरकारी उपभोक्ताओं से प्रारंभिक प्रतिभूति को वसूल नहीं कर सकी थी। यू ई आर सी ने कम्पनी द्वारा उचित औचित्य न दे पाने के कारण व्यय की विभिन्न राशियों को स्वीकार नहीं किया। कम्पनी ने वर्तमान एवं पुराने बकाया राजस्व की वसूली हेतु लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व संग्रहण कम हुआ। कम्पनी दोषी उपभोक्ताओं के विरुद्ध समय पर एवं उचित कार्यवाही नहीं कर सकी

⁴³ अनआथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।

⁴⁴ प्रत्यक्ष रूप से की गई चोरी -1,147 एवं यू यू ई/बिजली की अनाधिकृत उपभोग शण्ट डिटेक्टरेड मामले-656 ।

⁴⁵ एरियल बन्च कन्डक्टर।

जिसके कारण बकायों में वृद्धि हुई। कम्पनी की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर रही और कम्पनी कुल आपूर्ति की गई ऊर्जा की बिलिंग करने में असफल रही।

अनुशंसाएं

कम्पनी विचार कर सकती है कि:

- दुर्विनियोजन से बचने के लिए बैंक समाधान विवरण मासिक आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित करना;
- राजस्व हानि से बचने हेतु सभी उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग, नियमित अन्तराल पर मीटर की शुद्धता की जाँच और समय से दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना;
- एच टी लाइन के कवरेज को बढ़ाकर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क के एच टी/एल टी अनुपात में सुधार करना;
- वास्तविक पुराने बकाया देयों का स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने एवं उसकी वसूली हेतु तुरन्त उपयुक्त कदम उठाये जाने के लिए अवधिवार पुराने बकाया देयों की पहचान करना;
- वसूल की गई धनराशि में से चालू वर्ष और पुरानी बकाया देयों को अलग करना सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली की स्थापना करना;
- अनियमितताओं/त्रुटियों के जोखिम को कम करने हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की सुदृढकरण; एवं
- बिजली की चोरी से बचने हेतु चोरी आशंकित वाले क्षेत्रों में एरियल बन्च केबल लगाना।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष अगस्त 2013 में सरकार को भेजे गए। जवाब प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2013)।

अनुपालन लेखापरीक्षा

कुमाँऊ मण्डल विकास निगम

3.3 कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहन

निगम राज्य के कुमाँऊ क्षेत्र में पर्यटन प्रोत्साहन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका। इसकी सुविधाओं को उपयोग करने वाले पर्यटकों का प्रतिशत (5.29 प्रतिशत) नगण्य था। निगम के पास प्रचार के लिए कोई रणनीति नहीं थी। अपर्याप्त योजनाओं के कारण ही ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। वर्ष 2005 से 2008 की अवधि के दौरान निगम ने ₹ 2.12 करोड़ के व्यय से 20 पर्यटक सूचना केन्द्र (प सू के) का निर्माण कराया जिसमें से ₹ 0.97 करोड़ से निर्मित 9 प सू के बेकार अवस्था में थे। इसके अलावा, सड़क और बुनियादी सुविधाओं के बिना ₹ 1.42 करोड़ की लागत से निर्मित एक पर्यटक विश्राम गृह बेकार अवस्था में था।

3.3.1 प्रस्तावना

कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड (निगम) को कुमाँऊ क्षेत्र के सभी छः जिलों⁴⁶ में पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तत्कालीन उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखण्ड सरकार के पर्यटन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, राज्य सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित (अगस्त 1976) किया गया था। निगम की पर्यटन संबंधी गतिविधियों को विस्तृत रूप से दो श्रेणियों, प्रोत्साहन (प्रमोशनल) गतिविधियों और ढांचागत गतिविधियों में वर्गीकृत किया गया है। निगम, 47 पर्यटक

⁴⁶ नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर तथा चम्पावत।

विश्राम गृह (प वि गृ) और कैन्टीन, जिनमें से पाँच⁴⁷ अनुबंध के आधार पर संचालित हो रहे हैं, 20 पर्यटक सूचना केन्द्र (प सू के), जिला नैनीताल के पदमपुरी और आदि कैलाश में पर्यटन गाँवों के विकास, टनकपुर (जिला चम्पावत) में पर्यटन उन्मुख हस्तकला उद्योग एवं दीनापानी (जिला अल्मोड़ा) में शिल्प केन्द्र के विकास, संवर्धन, विपणन और संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह साहसिक पर्यटन संबंधी गतिविधियों जैसे जल क्रीड़ाओं, शीतकालीन खेलों, पैराग्लाइडिंग आदि एवं स्थानीय और पर्यटकों के प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहित करता है।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान निगम द्वारा कुमाँऊ क्षेत्र में पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए जो आवश्यक बुनियादी ढाँचा और अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान और संचालित की गई थी, के आकलन के लिए लेखापरीक्षा सम्पन्न की गई थी। अप्रैल 2013 से जून 2013 के मध्य लेखापरीक्षा सम्पन्न की गई। लेखापरीक्षा में जिला नैनीताल में स्थित प्रधान कार्यालय के साथ-साथ 47 प वि गृ में से 13 प वि गृ के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई थी, जिनका चयन प्रतिस्थापना नमूना तकनीकी के साथ सरल यादृच्छिकता के आधार पर किया गया था।

3.3.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.2.1 पर्यटक विश्राम गृह (प वि गृ) में न्यून अधिभोग

निगम ने कुमाँऊ क्षेत्र में 47 प वि गृ संचालित किए तथा उनको लाभ प्रदता, स्थिति और अधिभोग के आधार पर तीन श्रेणियों 'अ', 'ब' और 'स' में विभक्त किया गया है। वर्ष 2008-12 की अवधि के दौरान कुमाँऊ क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या 14.52 लाख से बढ़कर 19.11 लाख (31.61 प्रतिशत) हो गई। तथापि, निगम पर्यटकों के बड़े हुए अन्तर्वाह से लाभ नहीं उठा सका। वर्षवार विवरण तालिका 3.3.1 में दिया गया है:

तालिका- 3.3.1

बढ़ी हुई पर्यटक अन्तर्वाह का विवरण

(पर्यटकों की संख्या लाख में)

कैलेंडर वर्ष	2008	2009	2010	2011	2012
कुमाँऊ क्षेत्र में पर्यटकों का आगमन	14.52	16.77	17.45	17.76	19.11
प वि गृ का अंश	1.10	1.13	1.11	1.08	1.01 ⁴⁸
निगम का अंश (प्रतिशत में)	7.58	6.74	6.36	6.08	5.29

स्रोत: निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि जनवरी 2008 से दिसम्बर 2012 की अवधि के दौरान कुमाँऊ क्षेत्र में 85.61 लाख अन्तर्वाह पर्यटकों की संख्या के विरुद्ध प वि गृ में 5.43 लाख (6.34 प्रतिशत) पर्यटक ही आए। श्रेणी 'अ' के प वि गृ की कुल औसत अधिभोग 30.30 से 37.88 प्रतिशत, श्रेणी 'ब' के प वि गृ की 25.78 से 31.84 प्रतिशत तथा श्रेणी 'स' के प वि गृ की 17.56 से 20.81 प्रतिशत के मध्य थी। न्यून अधिभोग के कारण निम्न थे:

- दूरस्थ क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं, जैसे कार पार्किंग, पहुँच मार्ग आदि का अभाव;
- ऐसी सुविधाओं का अभाव जो कि पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद करती जैसे बिजली की निरन्तर आपूर्ति के लिए जनरेटर, स्वास्थ्य क्लब, इन्टरनेट, इन्डोर खेल आदि;
- कक्षाओं का दयनीय रखरखाव सहित सेवाओं की गुणवत्ता में कमी (जैसे सीवेज समस्या, समुचित सफाई की कमी आदि); और

⁴⁷ कोसी, कालाढूंगी, मनीला, मोनाल और पूर्णागिरी।

⁴⁸ अक्टूबर 2012 तक।

- प्रचार के अप्रचलित तरीके (रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड जैसे स्थानों पर साइन बोर्डों का न होना), विज्ञापनों को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित न करवाना।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2013)।

3.3.2.2 पर्यटक विश्राम गृहों (प वि गृ) की कार्य प्रणाली

निगम द्वारा सभी प वि गृ को उनकी लाभ प्रदता, स्थिति और अधिभोग के आधार पर तीन श्रेणियों (अ, ब और स) में श्रेणीबद्ध किया गया है। वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान प वि गृ के निष्पादन का श्रेणीबद्ध विश्लेषण तालिका 3.3.2 में दिया गया है।

तालिका - 3.3.2

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	प वि गृ की श्रेणी		
		अ	ब	स
1.	प वि गृ की संख्या ⁴⁹	8	13	21
2.	वास्तविक टर्नओवर	22.75	16.93	6.38
3.	अन्य आय	0.97	0.38	0.36
4.	कुल व्यय	14.85	14.54	9.18
5.	स्थापना व्यय	7.76	8.17	5.83
6.	परिचालन बिक्री स्थापना व्यय को छोड़कर (2+3-5)	15.96	9.13	0.92
7.	लाभ/(-) हानि (2+3-4)	8.87	2.77	(-) 2.44
8.	टर्नओवर पर स्थापना व्यय का प्रतिशतता	34.11	48.27	91.28

स्रोत: निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान श्रेणी 'स' के प वि गृ ने कुल ₹ 2.44 करोड़ की हानि उठाई। 'अ', 'ब' और 'स' श्रेणी के प वि गृ की परिचालन बिक्री स्थापना व्यय को छोड़कर क्रमशः ₹ 1,596.91 लाख, ₹ 913.91 लाख और ₹ 91.69 लाख थी। 'ब' एवं 'स' दोनों श्रेणी के प वि गृ में स्थापना व्यय उच्च थे जो टर्नओवर का क्रमशः 48.27 तथा 91.28 प्रतिशत थे। आगे, यह पाया गया कि निगम ने हानि उठाने वाले प वि गृ के कार्याकल्प हेतु कोई रणनीति नहीं बनाई और इस सम्बन्ध में निगम द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। 'स' श्रेणी के प वि गृ में लाभ अर्जित करने के लिए, बुनियादी सुविधाओं/सेवाओं और प्रचार में सुधार करके स्तर को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। यह इंगित करने पर प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जून 2013) कि प वि गृ की बढ़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.3.2.3 पर्यटक विश्राम गृहों (प वि गृ) के संचालन में परिहार्य नुकसान

निगम मुख्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रदर्शित है कि 'स' श्रेणी के छः प वि गृ⁵⁰ में अन्तिम पांच वर्षों, अप्रैल 2008 से मार्च 2013 की अवधि के लाभ-हानि में निरन्तर हानि थी जिसे तालिका 3.3.3 में दिखाया गया है।

⁴⁹ 5 प वि गृ को छोड़कर, जो किराये पर थी।

⁵⁰ चयनित प वि गृ के अलावा।

तालिका - 3.3.3

(₹ लाख में)

प वि गृ के नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
अल्मोड़ा	- 4.59	- 4.30	- 12.76	- 21.97	- 9.35	- 52.97
बागेश्वर	- 1.39	- 4.31	- 5.28	- 10.52	- 6.41	- 27.91
चम्पावत	- 3.38	- 6.87	- 9.75	- 7.61	- 9.02	- 36.63
दीनापानी	- 0.69	- 0.41	- 3.59	- 4.31	- 6.23	-15.23
खैरना	- 5.57	- 2.01	- 2.02	- 5.70	- 4.12	- 19.42
लोहाघाट	- 5.03	- 1.14	- 4.67	- 5.60	- 6.13	- 22.57
योग	- 20.65	- 19.04	- 38.07	-55.71	- 41.26	- 174.73

स्रोत: निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि निगम को उपर्युक्त उल्लेखित प वि गृ के संचालन में ₹ 1.75 करोड़ की हानि हुई। यह भी देखा गया कि निगम ने आगे की हानियों से बचने के लिए पाँच⁵¹ अन्य हानि उठानेवाली प वि गृ को अनुबंध के आधार पर दे दिया था। अनुबंध के अनुसार, प वि गृ के संचालन व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किये जाने हैं और निगम को एक निश्चित धनराशि देनी है। यह विकल्प इन छः प वि गृ के ₹ 1.75 करोड़ की हानि को बचाने के लिए भी लागू किया जा सकता था।

यह इंगित करने पर, निगम ने बताया (जून 2013) कि इन प वि गृ को लाभ पर संचालित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और यदि वे लाभ अर्जित करने में विफल रहते हैं, तब वे भी अनुबंध के आधार पर संचालित की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि केवल प वि गृ की अधिभोगिता में वृद्धि के साथ ही हानि को कम किया जा सकता था।

3.3.2.4 प्रचार और पर्यटन विपणन

पर्यटन व्यवसाय किफायती और आरामदायक सुविधाएं/सेवाओं को प्रदान करने के अतिरिक्त पूर्णतः प्रचार पर भी निर्भर करता है। प वि गृ में पर्यटकों के अन्तर्वाह में वृद्धि हेतु प्रचार के लिए एक प्रोत्साहन नीति तैयार करने की आवश्यकता थी। इसमें, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और राज्य के अन्य प्रवेश बिन्दुओं पर साइन बोर्ड, महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग का प्रदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और संगोष्ठियों के माध्यम से व्यापक प्रचार शामिल किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निगम द्वारा अपनी प वि गृ के प्रचार के लिए कोई रणनीति नहीं सुनिश्चित की गयी थी। यह आरक्षण केन्द्रों और प वि गृ पर पार्को के वितरण तक ही सीमित रही। वर्ष 2008-13 के दौरान सिर्फ स्थानीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन पर ₹ 51.78 लाख का व्यय किया गया। आगे, अभिलेखों के विश्लेषण में यह पाया गया कि कुमाँऊ क्षेत्र में पर्यटकों के कुल अन्तर्वाह के सम्बन्ध में प वि गृ में की प्रतिशतता और संख्या दोनों ही मामलों में 2008-09 में 7.58 प्रतिशत (1.10 लाख पर्यटक) से वर्ष 2012-13 में 5.29 प्रतिशत (1.01 लाख पर्यटक) तक घट गई थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि उपरोक्त वर्णित गतिविधियों को शुरू करने के लिए निगम द्वारा योजनात्मक रणनीति के साथ सरकार से कभी भी सम्पर्क नहीं किया गया। इस प्रकार, निगम अपर्याप्त प्रचार के कारण कुमाँऊ क्षेत्र की पूर्ण पर्यटन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सका था।

इंगित किए जाने पर, निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2013) और कहा कि मौजूदा प्रचार और विपणन पर्याप्त नहीं थे।

⁵¹ कोसी, कालाहूँगी, मनीला, मोनाल और पूर्णागिरी।

3.3.2.5 साहसिक पर्यटन

कुमाँऊ क्षेत्र में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए निगम विभिन्न साहसिक गतिविधियों का आयोजन करता है जैसे राफ्टिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, पैराग्लाइडिंग, स्नो स्केटिंग इत्यादि और पर्यटकों एवं स्थानीय गावों के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण भी देता है जैसा तालिका 3.3.4 में दिखाया गया है:

तालिका - 3.3.4

(₹ लाख में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
निगम व्यवसाय (साहसिक पर्यटन)	5.32	5.65	7.13	6.86	6.70
निगम का लाभ	2.64	1.26	2.09	1.02	1.43
प्रशिक्षित की गई प्रतिभागी (संख्या में)	408	242	755	504	225

स्रोत: निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निगम ने वर्ष 2008-13 के दौरान ₹ 23.22 लाख व्यय के सापेक्ष ₹ 8.44 लाख का लाभ अर्जित किया। निगम ने कुल 2,134 प्रतिभागियों⁵² के सापेक्ष 1,622 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया। हालांकि अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि रिवर राफ्टिंग के अतिरिक्त निगम पैराग्लाइडिंग और स्नो स्केटिंग गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित नहीं कर सका था तथा निगम द्वारा वर्ष 2011-12 से रॉक क्लाइम्बिंग नहीं कराई गई। रिवर राफ्टिंग में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को छोड़कर, अन्य गतिविधियों में उच्च जोखिम तत्व के शामिल होने के उपरान्त भी प्रतिभागियों का बीमा नहीं कराया गया था। आगे, निगम ने प्रबन्धक (साहसिक पर्यटन) को वर्ष 2012-13 में ₹ 7.22 लाख का अग्रिम रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, पैराग्लाइडिंग इत्यादि के संचालन हेतु दिया। यह अग्रिम पूर्व में उसी उद्देश्य के लिए वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान दिए गये अग्रिम⁵³ ₹ 19.99 लाख को समायोजित किए बिना दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2013 तक ₹ 27.21 लाख का समायोजन नहीं हुआ जो कि सामान्य वित्तीय नियमों के विरुद्ध था।

निगम ने कहा (मई 2013) कि पैराग्लाइडिंग का आयोजन भूमि की अनुपलब्धता के कारण एक निजी संगठन (हिमालयन एडवेंचर) के साथ संयुक्त रूप से किया गया और स्नो स्केटिंग का प्रशिक्षण अपर्याप्त बर्फबारी और निगम में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण आयोजित नहीं किया जा सका। यह भी आश्वासन दिया गया था कि साहसिक गतिविधियों के सभी प्रतिभागियों का बीमा आगे से किया जाएगा। प्रबन्धन द्वारा (जून 2013) बताया गया कि ₹ 27.21 लाख के प्रमाणक प्राप्त हो चुके थे जो कि समायोजन प्रक्रिया में हैं।

3.3.2.6 ग्रामीण पर्यटन

जिला नैनीताल के पदमपुरी और आदि- कैलाश में पर्यटन गांवों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निगम को ₹ 100 लाख की स्वीकृति (दिसम्बर 2006) प्रदान की गई। स्वीकृति अनुसार, निगम द्वारा हार्डवेयर के कार्य जैसे लॉग हट्स, सामुदायिक भवन, शिल्प केन्द्र के निर्माण, गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) से लिखित वचनबद्धता प्राप्त करने के बाद शुरू होना था, जो कि गांवों (लॉग हट्स) का संचालन करेंगे राज्य सरकार आदेश (26 मार्च 2007)। आगे, लॉग हट्स संचालन हेतु अधिकृत एन जी ओ⁵⁴ को सौंपने थे जैसा कि सरकारी आदेश (24 अप्रैल 2009) में दिया गया था जिनके द्वारा ग्रामीणों को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और शिल्प कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करना था।

⁵² 512 पर्यटक + 1,622 स्थानीय बेरोजगार युवा।

⁵³ ₹ 4.35 लाख (2007-08), ₹ 1.43 लाख (2008-09), ₹ 6.33 लाख (2009-10), ₹ 2.74 लाख (2010-11) एवं ₹ 5.14 लाख (2011-12)।

⁵⁴ समर फाउंडेशन, नई दिल्ली।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम ने ₹ 100 लाख के व्यय से पदमपुरी और आदि कैलाश में हार्डवेयर/लॉग हट्स का निर्माण (दिसम्बर 2008) एक गैर सरकारी संगठन से इन पर्यटन गांवों के संचालन के लिए अपेक्षित वचनबद्धता प्राप्त किए बिना ही कर दिया जो कि स्वीकृति आदेश के प्रावधान का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, इन लॉग हट्स को दिसम्बर 2008 से पदमपुरी और आदि कैलाश के ग्रामीणों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एन जी ओ को हस्तान्तरित नहीं किया जा सका था। ये लॉग हट्स बेकार अवस्था में थे और इनके मूल्य में भी ह्रास हो रहा था।

इंगित किए जाने पर, निगम ने बताया (जून 2013) कि इन हार्डवेयर के संचालन और रखरखाव के लिए कोई भी दिशा निर्देश अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वीकृति आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि हार्डवेयर का निर्माण, एन जी ओ से इसके संचालन के लिए लिखित वचनबद्धता लेने के पश्चात ही शुरू होना था, जिसको नजर अंदाज किया गया था। इस प्रकार अपर्याप्त नियोजन के कारण ही, ₹ 100 लाख व्यय के बाद भी ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका।

3.3.2.7 पर्यटन आधारित हस्तशिल्प उद्योग का प्रोत्साहन

पर्यटन नीति के अनुसार, पर्यटन आधारित हस्तशिल्प उद्योग प्रोत्साहन के लिए क्षेत्र की पारम्परिक हस्तकलाओं और शिल्प पर आधारित पर्यटन चिह्न का विस्तृत पैमाने पर उत्पादन प्रोत्साहन और राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। निगम ने प वि गृ टनकपुर में एक शिल्प केन्द्र के विकास के लिए दस दुकानों के निर्माण (जुलाई 2006) और प वि गृ के उन्नयन का प्रस्ताव दिया। भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए ₹ 84.17 लाख की राशि स्वीकृत (फरवरी 2007) की गई।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि दुकानों का निर्माण कार्य सितम्बर 2008 में ₹ 60.92 लाख की लागत से पूरा किया गया था। तथापि, आवंटी द्वारा इन दुकानों को शिल्प केन्द्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया। दस दुकानों में से, पाँच दुकानें जीवन बीमा निगम को 9 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई थी और शेष अन्य को आवंटित थी जो परिसर से कोई भी शिल्प सम्बन्धी गतिविधि का संचालन नहीं कर रही थी, जैसा कि स्वीकृति में प्रारम्भ में परिकल्पित किया गया था। इस प्रकार, पर्यटन आधारित हस्तशिल्प उद्योग प्रोत्साहन उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। यह इंगित किए जाने पर, निगम ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (जून 2013) कि शिल्प केन्द्र के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी लेकिन प्रतिउत्तर में कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई।

आगे, कुमाऊँनी शिल्प एवं सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने निगम को प वि गृ, दीनापानी (अल्मोड़ा) में शिल्प केन्द्र के विकास के लिए 15 दुकानें, बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं, बुकिंग काउन्टर और कार पार्किंग के निर्माण के लिए ₹ 35.44 लाख की राशि स्वीकृत किए (दिसम्बर 2006), जिसमें केवल 5 दुकानों का निर्माण अप्रैल 2008 में किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान ये शिल्प केन्द्र और संबद्ध सुविधाएं (मई 2013 तक) बेकार अवस्था में थीं और निगम द्वारा इन परिसम्पत्तियों के उपयोग के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए।

यह इंगित किए जाने पर, निगम ने बताया कि शिल्प केन्द्रों को स्थानीय लोगों में आवंटित करने के प्रयास किए गए थे लेकिन कोई भी व्यक्ति वर्णित उद्देश्यों के लिए इन दुकानों को किराए पर लेने के लिए इच्छुक नहीं था।

3.3.3 ढांचागत गतिविधियाँ

3.3.3.1 असंचालित पर्यटक सूचना केन्द्र (प सू के)

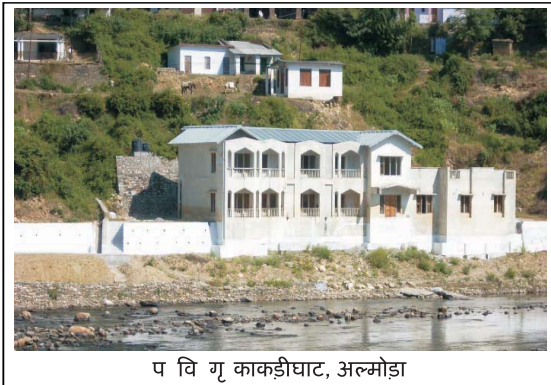
कुमाँऊ क्षेत्र में पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए, पर्यटकों के गंतव्य स्थानों के मार्ग पर बुनियादी सुविधाएं जैसे: विश्राम गृह, मनोरंजन, शौचालय, स्नान और पी सी ओ प्रदान करने के लिए प सू के का निर्माण किया जाना था। अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रदर्शित होता है कि राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड के कुमाँऊ क्षेत्र में 21 प सू के के निर्माण के लिए ₹ 215.34 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति (10 फरवरी 2004) प्रदान की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2005 से 2008 की अवधि के दौरान निगम ने ₹ 212.49 लाख के व्यय से 20 प सू के का निर्माण कराया। तथापि, 20 प सू के में से केवल 11 किराए पर दी गई थी और ₹ 96.64 लाख से बने 9 प सू के⁵⁵ बेकार अवस्था में थे। परिणामस्वरूप, पर्यटन को प्रोत्साहन देने और पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं/सूचनाएं प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया था। इंगित किए जाने पर, निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया (मई 2013)।

3.3.3.2 पर्यटक विश्राम गृह (प वि गृ) में निष्प्रयोज्य निवेश

राज्य सरकार द्वारा ₹ 82.35 लाख की लागत से काकड़ीघाट, अल्मोड़ा प वि गृ के निर्माण की स्वीकृति (मार्च 2006) प्रदान की गई जिसे निगम द्वारा अक्टूबर 2008 में स्वीकृत लागत से पूर्ण किया गया। हालांकि प वि गृ तक पहुँच मार्ग नहीं था, जो अभी तक (मई 2013) संचालन में नहीं थी। यद्यपि प वि गृ पूर्ण होने की तिथि से चार से अधिक वर्ष व्यतीत हो गए हैं। आगे, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय द्वारा ₹ 59.77 लाख की लागत से कटारमल, अल्मोड़ा प वि गृ के निर्माण की स्वीकृति (सितम्बर 2005) प्रदान की गई, जिसे निगम द्वारा मार्च 2008 में स्वीकृत लागत से पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प वि गृ पीने का पानी, बिजली, फर्नीचर और पहुँच मार्ग जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण ही असंचालित (मई 2013) थी।

निगम ने कहा (जून 2013) कि प वि गृ निर्माण के लिए स्थल चयन के समय वहाँ पर कोई पहुँच मार्ग नहीं था, इस प्रकार यह संज्ञान लिया गया था कि पर्यटक नदी पार करके प वि गृ तक जायेंगे। कटारमल, अल्मोड़ा के सम्बन्ध में निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (अक्टूबर 2013) कि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर था। इस प्रकार, प वि गृ त्रुटिपूर्ण नियोजन के परिणामस्वरूप धन अवरुद्ध हुआ जो कि अन्यत्र उपयोग किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सितम्बर 2013 में शासन को सन्दर्भित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।



प वि गृ काकड़ीघाट, अल्मोड़ा

⁵⁵ 1. विजयपुर 2. फटगली 3. गिंगरटोला 4. आमपड़ाव 5. काकड़ीघाट 6. चौखुटिया 7. द्वारहाट 8. मूलीगांव 9. घुंताघाट।

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.4 उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किये गये ऊर्जा क्रय अनुबन्ध

यू पी सी एल ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य 2793.45 एम यू अनशैडयूल्ड इन्टरचेंज (यू आई) ऊर्जा ग्रिड कोड के प्रावधानों का उल्लंघन किया जिसके लिए कम्पनी को यू आई अधिभार के रूप में ₹ 252.40 करोड़ अधिक भुगतान करने पड़े। अल्पकालीन ऊर्जा क्रय वर्ष 2009-10 में 138.92 एम यू से आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 1696.08 एम यू हो गयी। यू पी सी एल नियमित रूप से यू ई आर सी द्वारा तय की गयी सीमा से अधिक ओवरड्रॉल करता रहा जिसके परिणामस्वरूप ग्रिड असंतुलित हुआ।

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) उत्तराखण्ड राज्य में एक मात्र विद्युत वितरण कम्पनी है। यू पी सी एल उपभोक्ता माँग को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों⁵⁶ से विद्युत प्राप्त करती है जहाँ से राज्य को विद्युत का आवंटन किया जाता है तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (के सा क्षे उ) में उपलब्ध केन्द्रीय गैर-आवंटित कोटे⁵⁷ तथा अन्य बाह्य स्रोतों⁵⁸ से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त किये जाते हैं। लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए आरम्भ की गयी कि क्या विद्युत वितरण कम्पनी ऊर्जा आपूर्ति की विद्यमानता एवं उपभोक्ता हितों के मध्य संतुलन प्राप्त करने हेतु अपने ऊर्जा क्रय अनुबंधों (उ क्र अ) के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सक्षम थी। लेखापरीक्षा अप्रैल से जून 2013 के मध्य शुरू की गयी। इसके अन्तर्गत यू पी सी एल द्वारा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों (स्व ऊ उ) के साथ यू पी सी एल मुख्यालय पर हुए उ क्र अ एवं नौ वितरण खण्ड जो उनसे सीधे तौर पर यू पी सी एल की तरफ से विद्युत क्रय कर रहे थे, में से पाँच वितरण खण्डों⁵⁹ की विस्तृत जाँच शामिल थी। उ क्र अ पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष आगामी प्रस्तारों में दिये गये हैं।

3.4.1 ऊर्जा क्रय प्रबन्धन

बेहतर ऊर्जा क्रय प्रबन्धन हेतु, कम्पनी को ऊर्जा मितव्ययी रूप से क्रय करनी पड़ती है और साथ ही साथ उसकी सर्वकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ती है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि ऊर्जा की मांग एवं क्रय के मध्य अंतर वर्ष 2008-09 में 78.38 एम यू से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 629.89 एम यू हो गया जैसा कि *परिशिष्ट 3.8* में वर्णित है। पुनश्च, यू पी सी एल चार प्राथमिक स्रोतों⁶⁰ से ऊर्जा क्रय करता है। यू पी सी एल ने दूसरे राज्यों की कम्पनियों के साथ 'बैंकिंग व्यवस्था'⁶¹ की है तथा यह अल्प-कालीन आधार पर ट्रेडिंग अनुज्ञापी/ऊर्जा बाजार आदि के द्वारा भी ऊर्जा क्रय करता है। यू पी सी एल ने मार्च 2013 तक 89 दीर्घ अवधि के उ क्र अ किये। इन वर्षों के दौरान, यू पी सी एल द्वारा विभिन्न स्रोतों से क्रय की गई ऊर्जा को नीचे तालिका 3.4.1 में दर्शाया गया है।

⁵⁶ केन्द्रीय उत्पादन स्टेशन ऐसी कम्पनियों के उत्पादन स्टेशन हैं जिनका स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्र सरकार करती है।

⁵⁷ ऊर्जा आवंटन राज्यों और संघ शासित प्रदेश को दो हिस्सों में आवंटित की जाती है जैसे स्थाई आवंटन 85 प्रतिशत और गैर-आवंटित ऊर्जा 15 प्रतिशत जो कि सरकार द्वारा अति महत्वपूर्ण/पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये होता है।

⁵⁸ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एन टी पी सी) नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन (एन एच पी सी) न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन (एन पी सी) इत्यादि।

⁵⁹ विद्युत वितरण खण्डों - बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुड़की (ग्रामीण), नई टिहरी और उत्तरकाशी।

⁶⁰ सी पी एस यू, यू जे वी एन एल और मुफ्त ऊर्जा, यू आई ओवरड्रॉल/अंडर ड्रॉल/अल्पकालिक अनुबंध/बैंकिंग और आई पी पी।

⁶¹ बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत ऊर्जा का समतुल्य विनिमय यूटिलिटी के बीच होता है। यह व्यवस्था ऊर्जा विनिमय के रूप में ही होती है तथा नकद लेन देन नहीं होता।

तालिका - 3.4.1

(एम यू में)

क्र.स.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2,715.12	2,970.93	3,488.52	3,400.13	2,966.00
2.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू जे वी एन एल) व निःशुल्क ऊर्जा	4,850.61	4,372.47	5,145.18	5,666.31	5,401.82
3.	यू आई ओवरड्रॉल/अण्डर ड्रॉल/अल्पकालीन अनुबंध/बैंकिंग	199.90	956.64	585.06	1,103.70	1,974.86
4.	स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक	88.59	151.83	231.47	298.77	505.52
योग		7,854.22	8,451.87	9,450.23	10,468.91	10,848.20

स्रोत: उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

पुनश्च, यू पी सी एल किसी भी ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए ग्रिड से अनशैडयूल्ड इन्टरचेंज⁶² (यू आई) भी कर सकता है। तथापि, यह ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए एक नियमित साधन नहीं है तथा अन्तिम उपाय का साधन मात्र ही होना चाहिए। निरन्तर यू आई ओवरड्रॉल अतिव्ययी होने के अतिरिक्त ग्रिड के असंतुलन को भी बढ़ाता है। ऊर्जा की कमी को यू आई ओवरड्रॉल, अल्पकालीन ऊर्जा क्रय तथा विद्युत कटौती के द्वारा पूरा करने में यू पी सी एल की स्थिति *परिशिष्ट- 3.8* में दी गई है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यू पी सी एल ने पिछले पांच वर्षों में ग्रिड से ऊर्जा के ओवरड्रॉल को बढ़ाकर ऊर्जा की कमी को पूरा किया। कम्पनी ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के मध्य 2,793.45 एम यूज अनशैडयूल्ड इन्टरचेंज (यू आई) ऊर्जा लेकर ग्रिड कोड के प्रावधानों का उल्लंघन किया जिसके लिए कम्पनी को यू आई अधिभार के रूप में ₹ 252.40 करोड़ अधिक भुगतान करने पड़े। साथ ही, अल्पकालीन ऊर्जा क्रय 2009-10 में 138.92 एम यू से आश्चर्यजनक रूप से 2012-13 में 1,696.08 एम यू हो गयी। विद्युत कटौती 2008-09 में 78.38 एम यू से बढ़कर 2012-13 में 629.89 एम यू हो गई जो राज्य की आर्थिक वृद्धि को अवरुद्ध करती है। समग्र रूप से, यू पी सी एल को पिछले पांच वर्षों के दौरान, अपनी ऊर्जा मांगों का 15 प्रतिशत से अधिक अनशैडयूल्ड इन्टरचेंज, अल्पकालीन ऊर्जा एवं ऊर्जा कटौती के माध्यम से प्रति इकाई औसत लागत से उच्च लागत पर पूरा करना पड़ा जो वर्ष 2012-13 में चिन्ताजनक रूप से बढ़कर 26.53 प्रतिशत हो गया जिससे बचा जा सकता था यदि दीर्घ अवधि ऊर्जा क्रय प्रबन्ध किये गये होते।

इसे प्रकाश में लाने पर प्रबन्धन ने कहा (जून 2013) कि यू जे वी एन एल की जल विद्युत उत्पादन की उपलब्धता, जो कि जल एवं वर्षा के अनिश्चित विकास पर ही निर्भर है, की अनिश्चितता के कारण ऊर्जा की प्रतिदिन की सटीक मांग का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। यह भी कहा कि दीर्घकालीन ऊर्जा क्रय हेतु निविदाएँ सितम्बर वर्ष 2009 में अगले 25 वर्षों हेतु आमन्त्रित की गयी थीं, जो 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी होना था। निविदा का सबसे न्यूनतम मूल्य ₹ 4.68 प्रति के डब्ल्यू एच था जो कि अमितव्ययी था। प्रबन्धन का उत्तर उचित नहीं है क्योंकि यू आई ओवरड्रॉल निरन्तर रूप से वर्ष 2008-09 में 392.67 एम यू से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 552.21 एम यू हो गया। इसके अतिरिक्त, अल्पकालीन अनुबंधों द्वारा क्रय की गयी ऊर्जा की प्रति इकाई औसत लागत न केवल यू पी सी एल द्वारा वास्तविक ऊर्जा क्रय की प्रति इकाई लागत से अधिक थी बल्कि सी ई आर सी की, भारत के अल्पकालीन ऊर्जा बाजार, वर्ष 2012-13 पर प्रतिवेदन में दिये गये प्रति इकाई दर से भी अधिक थी। इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों में, यू पी सी एल ने दीर्घकालीन अवधि के ऊर्जा क्रय अनुबंध हेतु मात्र एक बार सितम्बर वर्ष 2009 में ही निविदाएँ आमन्त्रित की। इस प्रकार निगम ने ऊर्जा क्रय के लिए अधिक मितव्ययी दरों को प्राप्त करने हेतु गम्भीर प्रयास नहीं किए। यू पी सी एल की अल्पकालीन अनुबंधों पर निर्भरता पिछले पांच वर्षों में बढ़ी जिसकी औसत लागत प्रति इकाई⁶³ की सीमा प्रति इकाई ₹ 4.02 से ₹ 7.72 के मध्य रही।

⁶² एक समय सीमा के अन्दर, उत्पादन स्टेशनों या विक्रेता के लिये, यू आई का तात्पर्य है कुल वास्तविक उत्पादन में से कुल निर्धारित उत्पादन को घटाना एवं विक्रेता या लाभार्थी के लिये कुल वास्तविक आहरण में से कुल निर्धारित आहरण को घटाना।

⁶³ ₹ 4.02 से ₹ 7.72 प्रति इकाई की सीमा की गणना प्रतिवर्ष औसत लागत पर की गई है। हालांकि, वास्तविक समय क्रय में लागत की सीमा ₹ 3.68 प्रति इकाई से ₹ 11.98 प्रति इकाई वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक रही है।

3.4.2 निर्धारित सीमा से अधिक ऊर्जा का ओवरड्रॉल

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी ई आर सी) ने अनशैडयूल्ड इन्टरचेन्ज प्रभार एवं सम्बन्धित प्रकरण विनियम, 2009 का नियमन किया जो 1 अप्रैल 2009 को प्रभावी हुआ था, जिसमें कहा गया कि सी ई आर सी के यू आई विनियमों के अन्तर्गत 1 अगस्त 2009 से उस अवधि के दौरान जब ग्रिड आवृत्ति 49.2 हर्ट्ज से नीचे हो, कम्पनियों पर लगाए गए यू आई प्रभार, वितरण कम्पनियों के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए आर आर) में मान्य नहीं होंगे। इसके अनुसार यू ई आर सी प्रति वर्ष आवृत्ति तय करता है जैसा कि तालिका 3.4.2 में दिया है जो यू पी सी एल को निर्धारित सीमा से बाहर ऊर्जा ओवरड्रॉल करने से रोकता है।

तालिका -3.4.2

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
यू ई आर सी द्वारा यू आई ओवरड्रॉल हेतु तय की गयी आवृत्ति जिससे बाहर होने पर यू आई अधिभार यू पी सी एल द्वारा वहन किए जाएंगे।	49.5 हर्ट्ज	49.2 हर्ट्ज	49.2 हर्ट्ज	49.7 हर्ट्ज	49.8 हर्ट्ज

स्रोत: उताखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।

राज्य भार निस्तारण केन्द्र (एस एल डी सी) पर रखी जाने वाली दैनिक लॉग बुक⁶⁴ की जाँच के दौरान, वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित आवृत्ति की 49.8 हर्ट्ज से अधिक कम आवृत्ति पर ऊर्जा का ओवरड्रॉल की घटनाएं दर्ज की गईं जो दर्शाती हैं कि यू पी सी एल नियमित रूप से यू ई आर सी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ओवरड्रॉल कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप ग्रिड का असंतुलन हुआ। आगे यह भी देखा गया कि यू ई आर सी ने यू पी सी एल से ओवरड्रॉल की गयी ऊर्जा की विवरण तथा वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 हेतु क्रमशः 49.2 हर्ट्ज तथा 49.7 हर्ट्ज से नीचे की प्रणाली आवृत्ति पर यू पी सी एल पर भारित किये गये यू आई अधिभार की सूचना मांगी थी। यही सूचना, लेखापरीक्षा में भी पिछले पाँच वर्षों में मांगी गयी थी किन्तु निर्धारित आवृत्ति से नीचे के ओवरड्रॉल का वितरण अभी तक, न तो लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया और न ही यू ई आर सी को।

यह तथ्य प्रकाश में लाने पर प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जून 2013) कि कुल यू आई अधिभार, ए आर आर में सम्मिलित किए जा रहे हैं तथा अभी तक, यू ई आर सी द्वारा कोई भी यू आई अधिभार अमान्य नहीं किया गया है। उत्तर उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यू पी सी एल ने निर्धारित आवृत्ति से बाहर भुगतान किए गए यू आई अधिभार का कोई भी विवरण यू ई आर सी को उपलब्ध नहीं कराया है। सिवाय इसके कि नियमित रूप से सीमा से अधिक ओवरड्रॉल किया जिससे ग्रिड असंतुलन हुआ।

3.4.3 ऊर्जा संचालन प्रबन्धन

ऊर्जा के संचालन प्रबन्धन में पायी गई कमियों की चर्चा नीचे की गयी है:

3.4.3.1 स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों (स्व ऊ उ) द्वारा आयात की गयी ऊर्जा का बिलिंग न करना

स्व ऊ उ को अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या शुरुआत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जो कि यू पी सी एल से क्रय की जाती है (ऊर्जा का आगम)। स्व ऊ उ के साथ किये गये अनुबंधों के अनुसार, यू पी सी एल, स्व ऊ उ द्वारा खरीदी गई ऊर्जा के लिए मासिक बिलों की, अपने सामान्य बिलिंग चक्र के द्वारा ऐसे तरीके से जैसा कि आयोग ने अपने नियमों में बताया है के अनुसार मांग करेगा। पुनश्च, यू ई आर सी अपने नियमों (जुलाई 2010) में कहता है कि उत्पादन केन्द्र द्वारा क्रय की गयी ऊर्जा, आयोग द्वारा अस्थायी आपूर्ति के लिए निर्धारित दरों के अनुसार प्रभारित की जाएगी। विद्युत वितरण खण्ड (ई डी डी) बागेश्वर, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी के अन्तर्गत आई पी पी के अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि:

- ई डी डी बागेश्वर अपने मासिक ऊर्जा खाते में, स्व ऊ उ (पर्वतीय पॉवर लिमिटेड) द्वारा फरवरी 2008, इसके ऊर्जाकरण की तिथि से जुलाई 2012 तक किये गये ऊर्जा के आयात को ऊर्जा के निर्यात (यू पी सी एल द्वारा क्रय की गई ऊर्जा) से समायोजित कर रही थी। यद्यपि, उत्पादन के विद्युतिकरण की तिथि के सम्बन्ध में सीलिंग प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनश्च, ऊर्जा को समायोजित

⁶⁴ दिनांक 27.02.2012 से 29.07.2012।

करने के स्थान पर, यू ई आर सी निर्देशों के अनुपालन में ऊर्जा के आगम के लिए पृथक मासिक बिलों को निर्गत किया जाना चाहिए था। स्व ऊ उ को एक उद्योग समझा जाना चाहिए था तथा मासिक स्थायी प्रभार भी लगाये जाने चाहिए थे। ऐसा करने में असफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 5.39 लाख की हानि हुई;

- ई डी डी पिथौरागढ़ की स्थिति में, स्वा ऊ उ के विद्युतिकरण (मई 2011) से मई 2013 तक मात्र एक बिल (फरवरी 2012 तक) दिया गया; और
- ई डी डी, उत्तकाशी की स्थिति में, स्व ऊ उ⁶⁵ (हनुमान गंगा हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट) के ऊर्जाकरण अर्थात् अप्रैल 2004 (अभिलेख मांगे गये किन्तु अभी भी प्रतीक्षित) से न तो कोई बिल दिया गया और न ही ऊर्जा के आयात का ऊर्जा के निर्यात से कोई समायोजन किया गया।

3.4.3.2 क्षमता, परिशुद्धता व ऊर्जा मीटरिंग की माप

स्व ऊ उ के साथ किए गए अनुबंधों के अनुसार, यू पी सी एल, उत्पादक कम्पनी के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में, यदि उत्पादन कम्पनी ऐसा चुनती है तो, सभी मीटरिंग उपकरणों की परिशुद्धता की जाँच, अनुबंध के चालू रहने के दौरान, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार करेगी।

वितरण खण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि पाँच स्व ऊ उ में से, दो स्व ऊ उ⁶⁶ में मीटर जाँच नियमित रूप से नहीं हुई थी जबकि तीन स्व ऊ उ⁶⁷ की स्थिति में उनके विद्युतिकरण से मार्च 2013 तक कोई भी मीटर जाँच नहीं हुई जो कि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन है। उचित व नियमित मीटर चैकिंग व जाँच के अभाव में, आई पी पी द्वारा निर्गत ऊर्जा की बिलिंग की परिशुद्धता संदेहजनक है। परिणामस्वरूप, ऊर्जा निगम के सम्बन्ध में भुगतान की गई राशि की प्रमाणिकता के विषय में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अक्टूबर 2013 में सरकार को भेज दिया गया। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

देहरादून
दिनांक

(सौरभ नारायण)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(शशि कांत शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

⁶⁵ प्राकृतिक आपदा (3 अगस्त 2012) में आई पी पी ध्वस्त हो जाने की सूचना दी गई।

⁶⁶ स्वास्ति पॉवर लिमिटेड और गुनसोला हाइड्रो पॉवर लिमिटेड, नई दिल्ली।

⁶⁷ हिम हाइड्रो पॉवर लिमिटेड, मोतीगढ़, पिथौरागढ़, उत्तम शुगर मिल, जे एस टेक्नोलोजीज और मेट्रो फ़ोजन, रुड़की।